जीवन और फसलों की बरबादी हो जाती है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि इतने बड़े पैमाने पर कैलेमिटी रिलीफ फण्ड दिया जाता है लेकिन यह उचित आदमियों को नहीं मिल पाता है। आज देखते हैं जब बाढ़ का पानी सब तरफ भर जाता है तो हेलीकाप्टर से, हवाई जहाज़ से, किश्तियों से सेना के जवानों द्वारा लोगों को खाने का सामान बांटा जाता है। हमें बाढ़ को परमानेंट रूप से रोकने के लिए योजना बनानी चाहिये। बांध बना कर छोटे छोटे हाइडल पावर स्टेशन बनाने चाहियें। नदियों के पेटे में जहां मिट्टी जम गई है उसको खोद कर ठीक करना चाहिये तब जाकर हम नदियों को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं यह जो बाढ़ की समस्या है इससे हमें युद्ध स्तर पर निपटने का इन्तज़ाम करना होगा। आज की दुनिया में यह कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। हमारे पास सामर्थ्य है, टेक्नोलोजी है, लोगों का सहयोग हमारे पास है, इस काम के लिए रुपया भी है। इसलिए अगर देश को बाढ़ की विभीषिका से बचाना है, परमानेंटली बाढ़ को रोकना है तो हमें वार फुटिंग पर कार्य करना होगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): With leave of the House, I will request the Parliamentary Affairs Minister to announce the Government Business for the next week.

ANNOUNCEMENT RE. GOVERNMENT BUSINESS FOR 16TH AND 17TH AUGUST 1990

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI JAGDEEP DHANKHAR): Sir, with your permission, I rise to announce that Government Business in this House for Thursday, the 16th and Friday the 17th August 1990 will consist of:

(1) Consideration and passing of the Participation of Workers in the Management Bill, 1990;

(2) Discussion on the resolution regarding proclamation issued in relation to the State of Jammu and Kashmir;

(3) Discussion on resolution seeking disapproval of the Armed Forces (Jammu and Kashmir) Special Power Ordinance, 1990;

(4) Consideration and passing of the Armed Forces (Jammu and Kashmir) Special Powers Bill, 1990, as passed by the Lok Sabha; and

(5) Consideration and passing of the National Commission for Women Bill, 1990, as passed by the Lok Sabha.

RESOLUTION RE. RECURRING FLOODS IN BIHAR—*Contd.*

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, श्रीमती कमला सिन्हा ने जो प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं इस समस्या पर थोड़ा और विस्तार से रोशनी डालना चाहूंगी। यह हकीकत है कि आजादी के 42 वर्षों के बाद भी हमारे देश के प्राकृतिक जल संसाधनों को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके चलते अगर बाढ़ से उत्पन्न विभीषिका को मैं दुष्यंत के शब्दों में व्यक्त करूं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। तो महोदय, हालत यह है कि हर वर्ष बाढ़ से हमारे देश की करोड़ों अरबों की सम्पत्ति का नाश होता है। इसी संदर्भ में श्रीमती कमला सिन्हा ने जो समस्याएं उठाई और नदियों के अन्तर्राज्यीय और अन्तर्राष्ट्रीय चरित्र को बताते हुए जिन समस्याओं का जिक्र किया उन्हीं समस्याओं से जोड़ते हुए मैं पश्चिम बंगाल की बात को रखना चाहूंगी कि किस तरह से बिहार में जब बाढ़ आती है तो उससे पश्चिम बंगाल भी प्रभावित होता है। बिहार की दामोदर नदी में जब जल बढ़ने लगता है और दामोदर बांध पर जब जल का दबाव और ज्यादा बढ़ने लगता है तो काफी मात्रा में जल बंगाल की ओर छोड़ दिया जाता है। इसके चलते बंगाल के कई जिलों बर्दवान, हुगली, बीरभूम आदि में करोड़ों रुपये की तबाही होती है, फसलें नष्ट हो जाती हैं। यह तो भयावह समस्या है इससे हर वर्ष पश्चिम बंगाल को गुजरना पड़ता है। मैं इस सदन का तथा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि पश्चिम बंगाल को हर वर्ष जिस विपदा का सामना करना पड़ता है उस विपदा

[श्रीमती सरला माहेश्वरी]

से बचायें और बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए फौरी तथा दीर्घकालिक कदम उठायें।

महोदय, देखा तो यह जाता है कि हम आधुनिक तकनीक की बात करते हैं, कम्प्यूटर और सुपर कम्प्यूटर की बात करते हैं लेकिन हमारी तकनीक और कम्प्यूटर हमारे प्राकृतिक जल संसाधनों पर क्यों नहीं लागू होते हैं। हकीकत यह है कि आज भी हमारा किसान बारिश न हो तो सिर्फ बादलों की ओर देखता है, भगवान की ओर देखता है कि कब बारिश कराये। हम आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल क्यों नहीं अपनी कृषि और सिंचाई के लिए कर पा रहे हैं।

मैं इस सदन का ध्यान एक और बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि चीन जैसा देश जो हमारे से बाद में आजाद हुआ और जो बाढ़ की इतनी भयावह समस्या से गुजरता रहा उसने भी आजादी के बाद समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद बाढ़ की समस्या का सही ढंग से समाधान किया। लेकिन हमारे देश के शासक वर्ग ने बाढ़ की समस्याओं की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया और ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल नहीं किया ताकि बाढ़ की समस्याओं से हम देश को बचा सकें और सिंचाई में भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके अपने किसानों की जो केवल वर्षा पर निर्भरता है उसको खत्म कर सकें। इसलिए महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि श्रीमती कमला सिन्हा जी ने जो प्रस्ताव रखा है इस प्रस्ताव में निम्नप्रकार से थोड़ा अंश जोड़ा जाए तो अच्छा रहेगा। प्रस्ताव की छठी लाइन में है...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You have not given any amendment. Have you? Then, are you suggesting to her?

श्रीमती सरला माहेश्वरी: मैं सिर्फ अपना सुझाव देना चाहती हूं कि अगर इसको इस प्रकार किया जाए तो बेहतर होगा। जहां पर सेन्टेंस लगातार चल रहा है वहां उसको खत्म किया जाए और उसकी जगह इस छठी लाइन में जोड़ दिया जाए— Similar is the problem of West Bengal. Particularly, the release of water from Damodar Dam during the monsoon has its disastrous effect on some of the districts of West Bengal.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Madam, this may require an amendment proper. I do not think it can go as it is.

श्रीमती सरला माहेश्वरी: श्रीमती कमला जी से मैं निवेदन करूंगी कि अगर उनको कोई आपत्ति नहीं हो क्योंकि बंगाल और बिहार जुड़े हैं, इसलिए उनसे निवेदन करूंगी कि...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Suggestions can go.

श्रीमती कमला सिन्हा: मैं आपसे और सरला माहेश्वरी जी से इतना निवेदन करना चाहूंगी कि यह तो ठीक है कि बंगाल और बिहार जुड़े हुए हैं, इधर से उत्तर प्रदेश भी बिहार से जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश भी जुड़ा हुआ है, उड़ीसा भी जुड़ा हुआ है और नदियां बहती हैं तो एक प्रांत की सीमा रेखा में खत्म नहीं हो जाती, वह धारा बहती रहती है जब तक समुद्र में मिल नहीं जाती है। तो मेरे प्रस्ताव का जो कन्टेक्स्ट था वह कन्टेक्स्ट ही बदल जाएगा अगर दामोदर की समस्याओं को जोड़ा जाएगा। बेहतर यह होगा कि आप अलग से इस पर बहस करायें। ताकि हम लोग उसमें शिरकत करें और आपकी जो मंशा है उसमें हम सब लोग आपकी भावना को जोड़ देंगे।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: वह तो ठीक है, लेकिन मैं समझती हूं कि इसके साथ जुड़ने से इसका परिदृश्य बल्कि और ज्यादा सशक्त होता। वैसे आपकी इच्छा है। तो मैंने यह सिर्फ सुझाव दिया।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर): आप अपने भाषण में सुझाव दीजिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: अच्छा मैं सिर्फ सदन से यह निवेदन करना चाहूंगी और सरकार का भी ध्यान दिलाना चाहती हूं।

THE VICE CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): The Government is here. They will take note of it.

श्रीमती सरला माहेश्वरी: तो मैं सरकार का भी ध्यान दिलाना चाहूंगी कि बिहार के साथ बंगाल को भी जो यह भयंकर समस्या का सामना करना पड़ता है उसकी ओर भी सरकार उचित ध्यान दे। धन्यवाद।

डा॰ रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आप जैसे राष्ट्र के विख्यात न्यायविद जो राज्य सभा के उपसभाध्यक्ष के आसन पर विराजमान हैं सारे सदन ने आपका स्वागत किया है

और मेरा सौभाग्य यह है कि जब आप इस सदन की अध्यक्षता कर रहे हैं तब मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका आपने दिया है। मैं विश्वास करता हूं कि आपकी अध्यक्षता में संसदीय कार्यों की जो विराट मर्यादा इस सदन की रही है वह और आगे स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी, इस तरह की आपकी अध्यक्षता का असर होगा। मैं पुनः स्वागत करते हुए श्रीमती कमला सिन्हा जो हमारे माननीय सदन की सदस्या हैं और उन्होंने जो संकल्प उपस्थित किया है "कि बिहार की अधिकांश नदियों के उद्‌गम स्थल नेपाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है, इस कारण बिहार राज्य निरंतर बाढ़ की चपेट में रहता है जिसके फलस्वरूप प्रति वर्ष बाढ़ से प्रभावित देश की कुल जनसंख्या का लगभग 56.67 प्रतिशत और बाढ़ से तबाह होने वाले कुल भू-भाग का 37 प्रतिशत बिहार राज्य का होता है, यह सभा राज्य में विशेषतः उत्तर तथा मध्य बिहार में विनाशकारी बाढ़ की वर्तमान स्थिति पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह इस राज्य को प्रति वर्ष बाढ़ से होने वाली तबाही से छुटकारा दिलाने के लिए प्रभावी उपचारी कदम उठाये" यह संकल्प इस सदन में इसलिए लाया गया है कि प्रति वर्ष बाढ़ आती है, प्रति वर्ष अतिवृष्टि या अनावृष्टि होती है, सूखा पड़ता है, नदियों में जल पलावन होता है और इस देश का नागरिक जो नदियों के किनारे बसा हुआ है वह तबाही में पड़ जाता है और प्रति वर्ष यह सब कुछ उसे झेलना पड़ता है। बाढ़ के संबंध में अनादि युग से जब से सृष्टि हुई है जय शंकर प्रसाद की "कामायनी" की प्रारंभिक पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूंगाः

"हिमगिरी के उतुंग शिखर पर, बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक सघन था, एक तरल था, एक तत्व की ही प्रधानता कहो, उसे जड़ या चेतन।"

जड़ और चेतना के बीच में प्रलय हुआ था और वहीं से कामायनी और मनु का सृजन हुआ। सारी मानवता का उद्‌भव हुआ और एक तत्व की ही प्रधानता उसमें है। वह तत्व प्राणों की प्रधानता है। प्राण तत्व वायु तत्व वह है। मौसम पर नियंत्रण नहीं हुआ है और मौसम विभाग हमारा बारिश, सूखा इन सब की भविष्यवाणी करता है तो मौसम विभाग का काम 6 महीने पहले हमको उसका ज्ञान कराने का हो जाए और सरकार उसमे कारगर कदम उठाए, इस तरह की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। जल ही जीवन है।

क्षितिज, जल पावक, गगन समीरा,
पंचतत्व यह अधम शरीरा।

क्षितिज, जल, अग्नि, आकाश और वायु से हमारा शरीर संचालित होता है। मानव शरीर समाज का निर्माण करते हैं, समस्त प्राणियों का शरीर संचालन होता है और प्रकृति पर जब-जब विजय करने की कोशिश इंसान ने की है, तब-तब वह मुंह की खाकर के गिरा है। 40-42 साल हुए, यह ऐसी समस्या है। जिसे दलीय धरातल से ऊपर उठ कर विचार करने की आवश्यकता है। प्रति वर्ष बाढ़ आती है। उस बाढ़ के बारे में हमारी बहिन कमला सिन्हा जी ने कहा कि सोन नदी के पानी को उत्तर प्रदेश में रोकना होगा। नदी की धारा को रोकना और मोड़ना बिग्लों का ही काम होता है। एक भागीरथ पैदा हुए, जिन्होंने नदी की धारा को मोड़ दिया था कि देव नदी गंगा को धरती पर......

श्रीमती कमला सिन्हाः शायद उन्होंने मेरी बात को या तो सुना नहीं, या तो समझा नहीं, मैंने यह कतई नहीं कहा कि सोन नदी को उत्तर प्रदेश में रोक दिया जाए। मैंने कहा कि बाण सागर योजना से रिहंद डैम के द्वारा सोन के पानी को रोका जा रहा है। जब बिहार को जरूरत होती है, तब नहीं दिया जाता है, खरीफ फसल के लिए जब बरसात में अधिक पानी होता है, तो हमें कहने के लिए पानी छोड़ दिया जाता है।

डा० रत्नाकर पाण्डेयः मैं पहले से ही समझ रहा हूं कि रोकने की बात हुई। मैं तत्व समझता हूं, व्याख्या सारा देश समझता है।

उत्तर प्रदेश और बिहार का बड़ा मधुर संबंध है। अगर बिहार न होता, तो लव-कुश की सृष्टि न होती, राम और जानकी का देवता के रूप में पूजन न होता और उस मधुमय संबंधों के धरातल पर मैं कहना चाहूंगा कि देश में प्रांत तो बंटे हैं, प्रांत-वाइज़ हमने बनाया है, यह स्टेट सबजेक्ट है। जहां सरकार फंसती है, वहां कहते हैं कि यह स्टेट का सबजेक्ट है।

तो स्टेट का चीफ मिनिस्टर या जो शासक दल है, उसे अधिक चिंता होती है, अपने क्षेत्र में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, चाहे बाढ़ की हो या अनावृष्टि की या किसी चीज की हो। तो जो एक नदी के जल के बंटवारे को लेकर के इस देश में हजारों डेज की मीटिंग हो गई, करोड़ों रुपये खर्च हो गये और हर जगह अपने-अपने क्षेत्र के लिये संघर्ष और युद्ध चल रहा है, हाई-लेवल टैक्नालोजी मिशन की योजना की बात हुई है।

हमारे नेता, राजीव गांधी ने, प्रधान मंत्री के रूप में

[डा॰ रत्नाकर पाण्डेय]
जो कुछ इसके लिए किया है, आप क्या कर रही हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है? हमने तो नहीं किया था, इसलिए हम तो यहां आकर बैठ गये।

हमने ऐसी टैक्नालोजी डिवेलप करनी चाही, जो बाढ़ को नियंत्रित करे और उस बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक रूप से सम्पन्नता होनी चाहिए।

पंचवर्षीय योजना, प्लानिंग कमीशन को आप चीजें भेजेंगे और वहां से कह देंगे कि इस मद में पैसा नहीं है। तो हम लोग जो राष्ट्र के इस महान सदन में अपने भाव और उद्गार प्रकट करते हैं, उनके लिए आर्थिक संकोच बाधक बनता है और हमारे सारे उद्गार जो देश की जनता का उद्गार है, चाहे किसी भी दल का कोई सदस्य करता हो या स्वतंत्र सदस्य करता है, वह चिंतन की धरातल पर रह जाता है और प्रायोगिक रूप उसको नहीं मिलता है। उस प्रायोगिक रूप को समयबद्ध ढंग से, हाई टैक्नालोजी लेवल मिशन की जो योजना सरकार ने बनाई थी, उसको एक्सीक्यूट करने के लिए, उसको कार्यान्वित करने के लिए, वह योजना विश्व के जो बाढ़ ग्रस्त देश हैं, उनमें जो अपटुडेट टैक्नालोजी अपनाई जा रही है, उस को ध्यान में रखकर बनायी गयी है और उसे कार्यान्वित करने में आपकी सरकार यह सोचती है कि हम भी कुछ हैं। यह आप हर चीज में दिखाना चाहते हैं। महोदय, मैं एक उदाहरण दूंगा एजूकेशन पॉलिसी का। उस में वर्तमान प्रधान मंत्री ने 256 करोड़ को, तत्काल प्रधान मंत्री और विश्व मानवता के प्रतीक पुरूष राजीव गांधी के निर्देश पर, जो आज प्रधान मंत्री हैं उन्होंने 800 करोड़ किया। अब उसका रिव्यु हो रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में कटौती हो रही है। तो जब दरवाजे पर समस्या खड़ी हो जाती है तब हम उपाय करते हैं। हम भारतीयों की, हम राजनीतिज्ञों की यह प्रवृत्ति है कि तत्काल उपाय निकालकर जान छुड़ा लेंगे, कमीशन या कमेटी बना देंगे और कह देंगे कि कमेटी ने किया है। यह बंद होनी चाहिए।

महोदय, यह बिहार की ही समस्या नहीं है। यह ठीक है कि अधिकांश हिस्सा बिहार का डूब जाता है। बलिया, बनारस, गाजीपुर के उत्तर प्रदेश की स्थिति जो 13 जुलाई की है, वह मैं अति संक्षेप में रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, और बलिया जिलों में अब घाघरा नदी हर जगह खतरे के निशान को पार कर चुकी है। घाघरा नदी बलिया और बाराबंकी में खतरे के निशान से 40 सेंन्टीमीटर ऊपर बह रही है। इस बीच ककराही में सबसे ज्यादा 17.3 सेंटीमीटर बारिश रिकार्ड की गयी है। इसके बाद वाराणसी, गाजीपुर और बांकी का नंबर है। मौसम विभाग ने गोरखपुर और वाराणसी डिवीजन में मूसलाधार बारिश और दूसरे डिवीजनों में कुछ जगहों पर मध्यम और हल्की बारिश तथा बाढ़ की भयानक आशंका का अनुमान लगाया है।

महोदय, जो पर्वत पर बसे हुए अंचल हैं, उनको छोड़कर नदियां मैदानों में आती हैं। यह नदियों का देश है, देवताओं का देश है। हमने प्रकृति से अपनी संस्कृति को तादात्म्य किया है। चाहे अग्नि हो, चाहे वायु हो या जल हो—हमने प्रकृति को संरक्षक माना है। हम इसकी शक्ति के बल पर जिंदा रहना चाहते हैं और सारी दुनिया को जिंदा रखना चाहते हैं। महोदय, बाढ़ की विभीषिका की मौसम विभाग जो घोषणा करता है, मैंने उसकी बात की। इससे एक तो खेती का बड़ा भयानक नुकसान होता है। इस नुकसान को एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दो में विभाजित करते हैं। इस सबसे ऊपर प्रतिवर्ष हजारों आदमी मर जाते हैं और दूसरी ओर लोग चिल्लाते हैं कि नहरों से पानी आ रहा है। महोदय, विडम्बना यह है कि समन्वय नहीं है। एक दूसरे कामों में मिलान नहीं हो रहा है। ज्ञान और कर्म की एकता नहीं है। हमारे यहां हायेस्ट टैक्नोलोजी आयात हो जाएगी लेकिन उसको कार्यान्वित करने वालों में जब तक चारित्रिक पवित्रता नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। महोदय, देश को हर इंसान जानता है कि बाढ़ के पैसे का जो बांटना होता है, उस पैसे का दुरुपयोग करनेवाले नर पिशाच इस देश में हैं। महोदय, जब बाढ़ आती है तब पेड़ों पर रहकर सांप, इंसान और पक्षी सब एक साथ हो जाते हैं और अपने जीवन की रक्षा करते हैं। वे अपनी दुष्प्रवृत्ति को भूल जाते हैं। इस दुष्प्रवृत्ति की हमेशा के लिए समाप्ति जरूरी है।

महोदय, हमारा देश ऐसा है, जहां कि नदियां सुधा की धारा बहा रही हैं, जिसका मुकुट हिमालय है जिसके चरण निरंतर रत्नेश समुद्र धो रहा है। महोदय, जिसका मुकुट हिमालय है, जिसके चरण समुद्र पखार रहा है और नदियां अमृत की धारा बहा रही हों, आज उस देश में जल शक्ति का दुरूपयोग होता है या हम उसे दूषित करते हैं या वहां बाढ़ आती है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि गंगा प्रदूषण योजना चली है उसके तहत बनारस कमिश्नरी में बड़ा काम हो रहा है। हमारे नेता राजीव गांधी ने 50 करोड़ रुपया एक साथ दिया और 37 करोड़ अब तक सरकार की ओर से एलोट हो चुका है और उसमें काम हो रहा है। एक दिन मैं उसकी मीटिंग में बैठा था, कमीश्नर मीटिंग करते हैं, सारे लोगों को बुलाया जाता है, हमको बुलाया कि पांडेय जी,

आइए, कंसर्न अथोरिटी को बुलाते हैं। मैं उस मीटिंग में गया था। उसमें एक इंजीनियर था। कास्याम मरणाम मुक्ति, वहां काशी में मरने के लिए लोग जाते हैं, 24 घंटे चिता जलती रहती हैं क्योंकि काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है, ऐसी पौराणिक मान्यता है। वहां लाशें बहा दी जाती हैं किसी अभाव के कारण या कुछ और कारणों से, उसके लिए कछुए, मछली पाली जाएं, जो उच्छिष्ट और दुर्गन्धित मांस का भक्षण करें। इस पर उस इंजीनियर ने बताया, एरिगेशन डिपार्टमेंट या किसी और का इंजीनियर था, जिसको बारो किया था एडवाइस के लिए। उसने तीन-चार करोड़ का प्रोजेक्ट बताया कि जाल बिछाया जाएगा, जिससे मछली और मेंढ़क धारा में बहकर नहीं जाएंगे। मैंने कहा—यह कब तक चलेगा? तो कहा—इसकी गारण्टी नहीं ले सकता हूं। नीचे जाल बिछाकर उन्हें रोका जाए, इसकी व्यवस्था करने के लिए इंजीनियर तैयार नहीं है और तीन करोड़ की योजना बनाकर दे दी। मैंने कमीश्नर से कहा कि इसकी सर्विस की क्या जरुरत है, इसको अलग कर दीजिए क्योंकि इसकी इण्टेंशन खराब है। तो जो बैड-इंटेंशन के लोग हैं, चाहे वे सरकारी सेवा के क्षेत्र में हों, चाहे समाज-सेवा के क्षेत्र में हों जो बाढ़ का, दुर्भिक्ष का पैसा हड़प जाते है, सही जगह नहीं पहुंचाते हैं उनके लिए कोई सजा का प्रावधान बनाइए । ललाटेन लेकर बरसात में कहीं घूम रहे हैं, चटाई दबाकर घूम रहे हैं और बिल-बाऊचर कहीं और से बना रहे हैं। ऐसा हुआ है, निरंतर होता रहता है। इन चीजों को देखना जरूरी है, केवल भाषण कर देने से कि हम वेल्यू-बेस्ड हैं, मूल्यों की राजनीति करते हैं, मुद्दों की राजनीति करते हैं, यह चलने वाला नहीं है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि दल से ऊपर उठकर काम करना होगा, जो मानवीय विभीषिकाएं हैं, उन पर।

महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग बुलाई थीं, जिसमें सारे मुख्य मंत्रियों और एरिगेशन मिनिस्टर वगैरह आए थे। उसकी रिपोर्ट भी हमारे सामने है। उसमें मुख्य मंत्रियों ने, जिनमें बिहार के मुख्य मंत्री भी थे, उत्तर प्रदेश के भी रहे होंगे, सबने यह मांग की है कि एक स्थाई योजना बनानी चाहिए। जहां तीन-तीन ओर समुद्र बह रहा हो, जहां नदियों में बाढ़ आ रही हो, जल-संपदा का उपयोग हम नहीं कर पा रहे हों, उसके लिए योजना बनानी चाहिए। दुनियां में ऐसी कोई टेक्नोलोजी जरूर बनी है कि अशुद्ध जल को, खारे जल को शुद्ध करके हम सिंचाई के काम में ला सकते हैं। जहां तक मिट्टी का है, नई मिट्टी क्या आसमान से टपकेगी। नदियों की लाई हुई मिट्टी से जो फसल उत्पन्न होती है, उस मिट्टी की फसल कितनी उर्वरा होती है, कितने गुणा अधिक वह उत्पादन देती है। अगर कृषि मंत्री जी आज होते तो सदन को इस बारे में बताते, वह तो हैं नहीं हमारे उप-प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, जो गावों से जुड़े हुए हैं।

महोदय, नदियां, चाहे कावेरी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे गंगा हो, जमुना हो, चाहे सरस्वती हो, इन नदियों के जलों का आचमन करने से, सारे देश के जल को एक-साथ जोड़ने से और समुद्र के खारे जल को शुद्ध करने से आप इस देश की भुखमरी की समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके लिए आप कुछ सोचिए। क्या खाली भाषण कर देने से हम मान लेंगे कि सब हो गया? यहां दो सौ करोड़ रुपये की मांग है बिहार की, उत्तर प्रदेश की भी मांग आपके पास है। मैंने बढ़े विस्तार से विषय को रखा है, लेकिन अभी सब डेटा देकर के सदन की जानकारी को और विस्तृत कर सकता हूं, समय बहुत लगेगा।....**(व्यवधान)**....

मैं कह रहा था कि कोई योजना बनाइए मंत्री जी। जिसकी साख बनी रहती है उसको धन की कमी नहीं होती। भारत की साख राजीव गांधी ने बनाई थीं। आज विश्व के सामने आपकी सरकार की अस्थिरता का भी प्रश्न है। वर्ल्ड बैंक और जो फाइनेंसिंग एजेंसीज हैं वर्ल्ड की, वह आपको कितनी धनराशि देंगी? आज भी जैसे "मंडेला" का काम हमने किया, अफ्रीका को स्वतंत्र कराया और वहां आपने श्रेय लिया, उसी तरह से हम आपकी सहयोग करने को तैयार हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हमारे पास एक ऐसा नेता है जो दुनिया में किसी राष्ट्राध्यक्ष से कहेगा तो पैसे की कमी आपको नहीं होने पाएगी, लेकिन एक टैक्निकल्स की अच्छी कमेटी बनाकर सदन के सामने लाएं कि बाद का नियंत्रण करने के लिए आप यह स्थाई योजना ला रहे हैं और समुद्र के खारे पानी को शुद्ध करके, अनावृष्टि के नियंत्रण के लिए आप यह कहने जा रहे हैं। नदियों को एक दूसरे से जोड़कर कैसे उसके जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर देते हैं जहां अभाव है? यह सब कुछ हो और इसके लिए एक आचरण की पवित्रता चाहिए। आचरण की पवित्रता तब होती है जब भौतिकता से परे हो आदमी और शासक:

"सुख-दुख सरिस प्रशंसा गारि, सबसे प्रिय, सबके हितकारी"

कौन गाली दे रहा है कौन प्रशंसा कर रहा है जनता का हित किसमें है, यह शासक का कर्म होता है।

नदियों के, बाढ़ के इलाके से मैं आता हूं। बनारस

[डा॰ रत्नाकर पाण्डेय]

कमिश्नरी में बलिया, गाजीपुर, बनारस सब हैं और 1948 की बाढ़ भी मैंने देखी है। 1987 में भयंकर बाढ़ आई थी, मैं डाटा की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे नेता राजीव गांधी ने मैनेज किया था कितने लोग मरे थे? उस बाढ़ में 1967 के बाद उतने लोगों का निधन नहीं हुआ, न पशुधन का निधन हुआ। देश में न अन्नाभाव हुआ, न पैट्रोल का अभाव हुआ, न सार्वजनिक सेवाएं, जो सरकार की ओर से थीं, उनमें अभाव आया और आज इसी वर्ष जो बाढ़ आई है तो लोग त्राहि-त्राहि कर उठे हैं। यह कम्युनिकेशन गैप आपके बीच में, स्टेट गवर्नमैंट के बीच में है और सबसे बड़ी चीज यह है कि आपके पास धन है नहीं। कई वर्षों का डाटा उठाकर देखिए कि जितनी धनराशि बाढ़ नियंत्रण के लिए स्वीकृत की गई थी उसमें से 100 या 200 करोड़ रुपया बच गया है।

संत तुलसीदास ने जल के स्वभाव पर कहा है, उसको आप मोटो बनवाइए अपनी मिनिस्ट्री में टंगवा दीजिए जगह-जगह प्रचार कीजिए। वह मानवता के चिंतन के लिए भी है और बाढ़ के संबंध में भी है।....**(व्यवधान)**....

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): पाण्डेय जी, पहली बार सरकार ने कुछ काम नहीं किया था? ....**(व्यवधान)**....

डा॰ रत्नाकर पाण्डेय: पहली सरकार जो कर गई है, उसी पर आप जी-खा रहे हैं। आप लोग जो कर रहे हैं, उसका एक रूप कल वहां था। आप तो क्लास-स्ट्रगल इस देश में कराना चाहते हैं। वी॰पी॰ सिंह की कुर्सी बची रहे, इसके लिए वह किसी एक्सटैंड तक जा सकता है। मुझे छेड़िए मत।....**(व्यवधान)**....मैंने शुरू से ही दल से ऊपर उठकर बात करने की कोशिश की है। मैं नहीं चाहता कि इंट्रप्शन हो।....**(व्यवधान)**....

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल): आप दल से ऊपर उठे हैं, नेता से ऊपर नहीं उठे।

डा॰ रत्नाकर पाण्डेय : नेता से जो ऊपर उठ जाता है उसके पास पार्टी-करेक्टर नहीं होता है। हमारे नेता का चरित्र ऐसा है जिसमें गर्व के साथ हम कह सकें कि हमारा नेता भारत की जनता का और विश्व की दबी हुई, पिछड़ी हुई जनता का, इस धरती पर जितने नेता हैं उनका सिरमौर है राजीव गांधी। जिसको हमने निकाल दिया उसको आपने प्राइम मिनिस्टर बनाया है, वह आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। हमारे नेता की बात करने से पहले आप अपने दामन में झांककर देखिए। आपने हमारे दल से निकाले हुए व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया। ये आपका चरित्र है। आप पोलिटिकल एथैक्सि पर कैसे बात कर सकते हैं? महोदय, यहां, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नेहरूजी ने एक बार आचार्य नरेन्द्र देव से कहा था कि सारे लोग सरकार में हैं, आप भी आइए ताकि हम आपके ज्ञान का उपयोग कर सकें। तो उन्होंने जो पत्र लिखा मैं उसकी दो पंक्तियां यहां उद्धृत करना चाहता हूं—मैं देख रहा हूं कि मेरे सारे साथी सरकार में जा रहे हैं। जनतंत्र चलाने के लिए मजबूत सरकार होनी चाहिए उससे कई गुना अधिक मजबूत अपोजीशन होनी चाहिए। जैसे जुआ बैल के गले में पहनाया जाता है, हम आपको जुआ बनकर दिखाएंगे और आपको सांड की तरह अनियंत्रित नहीं चलने देंगे। हम आपको दिखाएंगे कि अपोजीशन का रोल क्या है"। वह रोल आज राजीव गांधी अदा कर रहे हैं और उस रोल के माध्यम से सारे विश्व की जनता यह देखेगी कि अपोजीशन का एक सबल जनतंत्र में क्या महत्व होता है। हम जहां भी रहें, राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं और जनता की सेवा करते रहेंगे।

श्री ईश दत्त यादव: आप बाढ़ पर भाषण दे रहे हैं या राजीव गांधी पर?

डा॰ रत्नाकर पाण्डेय: ये तो आपने छेड़ दिया है, आप न छेड़ते तो मैं बाढ़ पर ही बोलता । अब मैं तुलसीदास की एक पंक्ति का उद्धृत कर रहा हूं—

जग बहु नर सर सरिसम भाई,
जे निज बाढ़ि बढ़हिं जल पाई।

श्री कैलाश नारायण सारंग (मध्य प्रदेश): आप एक ही पंक्ति बार-बार क्यों दोहरा रहे हैं? कोई नई पंक्ति सुनाइए।

डा॰ रत्नाकर पाण्डेय: यह नयी है। एक और नयी पंक्ति अंत में सुना दूंगा। तो मैं कह रहा था कि—

जग बहु नर सर सरिसम भाई,
जे निज बाढ़ि बढ़हिं जल पाई।
सज्जन, सुकृत, सिन्धु सम कोऊ,
देखि पूर विधु बाढ़हि जेऊ।

तो समुद्र स्थिर रहता है। जब चन्द्रमा की किरणें पड़ती हैं **(व्यवधान)**

SHRI T.A. MOHAMMED SAQHY (Tamil Nadu): Mr. Vice, Chairman, Sir, I am not getting the translation. Let him

also translate it into English so that we can understand the meaning.

SHRI S.S. AHLUWALIA (Bihar): You can use your earphone.

SHRI T.A. MOHAMMED SAQHY: I am talking about the couplet. I do not get the translation.

DR. RATNAKAR PANDEY: You can use the headphone.

SHRI T.A. MOHAMMED SAQHY: I am talking about the couplet. I would like to understand the meaning.

DR. RATNAKAR PANDEY: I will explain it to you.

संसार में तालाब और नदी के समान बहुत से लोग होते हैं जो थोड़ी सी बाढ़ आने पर जैसे जल बढ़ जाता है उस तरफ बह जाते हैं लेकिन जो सज्जन लोग होते हैं वह अच्छा काम इस तरह से करते हैं जैसे समुद्र। समुद्र हमेशा स्थिर रहता है लेकिन जब चन्द्रमा की किरणें पड़ती हैं तो वह बढ़ने लगता है। तो इन पंक्तियों में मानव चरित्र की जल से तुलना की गई है।

संसार में सभी जीव बाढ़ से प्रभावित होते हैं — चाहे पशु हो, पक्षी हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, स्त्री हो या पुरुष हो। देश को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए सुझाव दिया गया कि पेड़ लगाए जाएं लेकिन पेड़ काट दिए गए। इस देश में सारे पहाड़ नंगे हैं, जंगल बुरी तरह से कट रहे हैं और बहुत तेजी से कट रहे हैं। आप जरा जाकर इस बात का पता लगाइए। मैं तो देख ही रहा हूं कि धुंआधार कट रहे हैं क्योंकि कोई प्रशासन नहीं है। सभी प्राकृतिक संपदाओं को विनष्ट कर दिया गया है। हमारे देश का एनवायरमेंट, वातावरण दूषित न हो इसके लिए मैं चाहूंगा कि कोई एक अच्छी योजना बनाई जाए। जब बाढ़ आती है तो गरीबों के घर गिरते हैं। इसके लिये मैं चाहूंगा कि कोई एक अच्छी योजना बनाइये और जब बाढ़ आती है, घर गिरता है किसी गरीब का, दिल टूटता है तो आवाज नहीं होती है। लेकिन जब अर्रा करके बाढ़ में नदी के किनारे के पेड़ गिरते हैं तो गांव का गांव बह जाता है। नदियां जब प्रवेश करती हैं गांव में तो प्रवाहित कर ले जाती हैं सारी जन, धन, सम्पत्ति सब कुछ और ऐसी परिस्थिति में हमने एक योजना दी है टैक्नोलोजी मिशन की आपको। उस योजना को रिव्यू मत कराइये। हमने पुख्ता ढंग से उसको बनाया था और आप अगर उसे पूरा करने की शुरूआत करते हैं तो आने वाले इतिहास में लिखा जायेगा कि आपकी सरकार ने उस पर कार्यवाही की। अगर केवल टाल देते हैं उस चीज को तो उसकी शुरूआत भी हम करेंगे आने वाले दिनों में और उसे पूरा करेंगे। बाढ़ में मांग तो बहुत होती है, पैसा आपके पास है नहीं, प्लानिंग कमीशन देगा नहीं, जो रुपया आपके पास सैंक्शन है कभी-कभी उसको खर्च नहीं कर पाते हैं तो एक व्यवस्थित ढंग से आप योजना बनाइये। प्रति वर्ष के बाढ़ की विभिषिका का सारा आंकड़ा रख करके कि क्या किया जाये, अधिक से अधिक राहत हम दे सकें देश को और समाज को और जो उसमें भ्रष्ट लोग हैं — चाहे मंत्री हों, चाहे मुख्य मंत्री हों, चाहे सैक्रेटरी हों, चाहें तहसीलदार हों, चाहे सफेदपोश क्षेत्रीय नेता हों उठा करके बंद करिये, कालिख पुतवा करके उनको गधे पर बैठा करके घुमाइये कि इसने बाढ़ का पैसा खाया है, इसने अनावृष्टि का पैसा खाया है। आप कर सकते हैं या नहीं? यह मेरी आकांक्षा है कि आप करें। लेकिन कर पायेंगे या नहीं यह भगवान जानता है क्योंकि आप भी नहीं जानते कि कल क्या होगा। इन शब्दों के साथ....(**व्यवधान**)

श्री अश्विनी कुमार (बिहार): कौन मंत्री सबसे पहले आयेगा सोच लीजिये। पिछली सरकार का ही मंत्री होगा सबसे पहले।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर): लैट हिम फिनिश।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: मैं समाप्त करूं इसके पहले, मैं गंगा के तट का रहने वाला हूं, अमृत नदी को माना गया है। हर साल गंगा में बाढ़ आती है, सारा कूड़ा-कचरा हर नदी में आता है, बह जाता है तो गंगा को शुद्ध रखा जाये और उसमें अपवित्र जल, कारखानों का जल या गंदगी मलमूत्र जल मिश्रित प्रवाहित न हो और लोग नदियों की स्वच्छता को बरकरार रखें, तभी कुछ आप कर सकते हैं और हम विश्वास करते हैं कि जो....(**व्यवधान**)

SHRI SHIV PRATAP MISHRA (Uttar Pradesh): On a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Point of order against whom? Against Dr. Pandey?

श्री शिव प्रताप मिश्र: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जो बाढ़ का प्रस्ताव आज कमला जी ने प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन हूं लेकिन इसमें बाढ़ की विभीषिका की जो चर्चा हुई उसका दायित्व प्रकृति के अतिरिक्त में

मानता हूं, सरकार पर है। उसको प्राकृतिक दोष पर डालकर के उसकी जिम्मेदारी से हमें नहीं हटना चाहिये। क्योंकि इसको... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर): पोइंट आफ आर्डर क्या है?

SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Sir, in the Indian history the Gupta Empire was called the 'Golden Age' because that was the *swarn yug* and through the annals of history we come to know that:

अनुगंगा प्रयागं च साकेतं मगधान् तथा।
एतान् जनपदान् सवनि् भोक्ष्यन्ते गुप्त वंशजाः।।

This means that during the Gupta Empire all the prominent cities were developed on the bank of the Ganga. Allahabad, which was called Prayag, Kashi and other cities were on the bank of the Ganga. Ayodhya, which is the point of dispute today, that is also on the bank of Sarju river.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): What is your point of order?

श्री अश्विनी कुमार: क्या कर रहे हैं ...(व्यवधान)

डा० रत्नाकर पाण्डेय: अतीत और वर्तमान को जोड़ रहे हैं।

श्री अश्विनी कुमार: हाउस की बात कीजिये, क्या बात कर रहे हैं। कल को स्वर्ग की बात करेंगे, हाउस की बात कीजिये।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: स्वर्ग को जाना है आपको भी।

श्री शिव प्रताप मिश्र: मैं अर्ज कर रहा हूं कि इसमें सरकार की जो अव्यवस्था है उसको आप प्राकृतिक दोष नहीं दे सकते हैं। जिस तरह से 1987 में बाढ़ आयी, जिसको कमला जी ने अभी स्वीकार किया है कि हमारे पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी ने उस समय 1987 में वहां जाकर के टैक्नोलोजी मिशन का प्रस्ताव किया था उसको आप पूरा कीजिये।

आज जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की, नेपाल की नदियां मगध में जाकर गिरती हैं बाढ़ में जितना अनुदान दिया जाता है उसका अपव्यय और दुरुपयोग न हो क्योंकि मगध की कीर्ति रही है। मौर्य काल में मगध से भारत का एकीकरण किया गया था जिस समय चाणक्य से मैगस्थनीज मिलने आया था। उस समय भी गंगा नदी थी परन्तु बाढ़ से हानि नहीं होती थी, क्योंकि शासन की व्यवस्था ठीक थी।

SHRI ASHWANI KUMAR: Sir, this is absolutely irrelevant and must be taken off the record.

SHRI SHIV PRATAP MISHRA: I am saying that misappropriation of funds should stop and these should be properly utilised by the Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): There is no point of order.

SHRI ASHWANI KUMAR: It is a misuse of point of order. Every thing should be expunged.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI MANUBHAI KOTADIA): If the hon. Member wants, he can participate in the debate. Let him participate in the debate.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): It is not a point of order.

DR. RATNAKAR PANDEY: Mr. Vice-Chairman, I am going to conclude.

अतीत और वर्तमान को जोड़ कर समन्वयवादी दृष्टि से आप काम करें इसका सम्मिश्रण किया है मिश्र जी ने, डोंट टेक इट लाइटली। मैं कहना चाहता हूं कि स्थायी व्यवस्था आप करें। प्रकृति को विनष्ट होने से बचाएं, भ्रष्टाचार से दूर रहें, सारे देश के जल का सही ढंग से उपयोग हो ताकि यह धरती शस्य श्यामला उर्वरा धरती भारत की जैसी रही है अतीत में, वही आज भी है। उसका अग्रगामी रूप बने। अंत में चार पंक्तियां पढ़ूंगा। बाढ़ का दृश्य बनारस में गंगा के तट पर खड़े होकर जो मैंने देखा है उसमें काफी बड़ी रहती है गंगा लेकिन उस पार पेड़ छोटे-छोटे दिखाई देते हैं, लहरें उत्ताल तरंगें लेती रहती हैं।

नदिया का यह गेहुआ रंग का मटमैला जल,
ऊपर छाये बादल,
कुछ झुकी बरौनी सी (बरौनी यानी आंख की पलक)
उस तट पर पेड़ खड़े, बिजली चमकी तो, दिखे,
चमका हर लहरों में काजल,
नदिया का यह गेहुआ रंग का मटमैला जल।

श्री ईश दत्त यादव: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आभारी हूं आपका कि आपने इस गंभीर विषय पर विचार रखने के लिए समय दिया। श्रीमती कमला सिन्हा ने जो इस सदन में संकल्प प्रस्तुत किया है वह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है और देश हित में है। यह देश की अत्यन्त ही गंभीर समस्या है बाढ़ की। यों तो दैवी आपदाएं इस देश को समय समय से पीड़ित और बर्बाद करती रही हैं लेकिन बाढ़ और सूखा दो आपदाएं ऐसी हैं जिससे जन-जीवन की, पशु की और फसल की तथा देश की धरती की बहुत हानि होती है। श्री पाण्डेय जी का भाषण मैं सुन रहा था। वह बाढ़ पर कम साहित्यिक बातें ज्यादा कर रहे थे और अपनी सरकार का गुणगान उससे अधिक कर रहे थे।

4.00 p.m.

सन् 1988 में आसाम में बड़ी भयंकर बढ़ आई थी। उस वक्त भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी इस देश के कर्णधार थे। आसाम में चूंकि विपक्ष की सरकार थी इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। विपक्ष के संसद सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल वहां राज्य सरकार के कहने पर गया था। माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में गया था। मैं भी अपने दल की ओर से उस प्रतिनिधि मंडल में गया था। आसाम में संभवतः 18 जिले हैं। उनमें से 17 जिले बाढ़ में डूबे हुए थे। हम लोगों ने पैदल चलकर, हेलीकाप्टर से और मोटर बोट से यह भयानक दृष्य देखा था। मैं पाण्डेय जी को स्मरण दिलाना चाहता था, लेकिन वे चले गये। उनकी सरकार ने कुछ नहीं किया। यह तो मैंने आसाम की बात कही। पूरे देश की स्थिति बड़ी खराब है। सुखे और बाढ़ से बराबर इस प्रकार की स्थिति हो जाया करती है। सूखा को तो रोका नहीं जा सकता है और हो सकता है उसका कोई वैज्ञानिक उपाय हो, लेकिन बाढ़ पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अगर इसकी स्थायी और मजबूत योजना बनाई जाए तो इसका हल हो सकता है। श्रीमती कमला सिन्हा जी ने कहा कि नदियां उत्तर से या पश्चिम से बहती हैं। प्रायः सभी नदियों की यह स्थिति है। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से जब ये नदियां बहती हैं और समुद्र तक जाती हैं तो ये प्रदेश ज्यादा बरबाद होते हैं। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं, सरकार के पास आंकड़े हैं और मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी और श्रीमती कमला सिन्हा जी ने भी सारे तथ्य प्रस्तुत किये हैं कि किस प्रकार से बरबादी होती है। मैं यह कह रहा था इसका कोई स्थायी निदान होना चाहिए। इसके लिए कोई बड़ी योजना बनाई जानी चाहिए ताकि लोग बाढ़ से पीड़ित न हो और बरबादी भी न हो। लेकिन पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। सूखा जब पड़ता था, मुझे स्मरण है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और भयंकर सूखा पड़ गया। सरकार ने हर गांव के सभापति को सौ-सौ रुपये बांट दिये और कहा कि पांच पांच कुंये अपनी गांव सभा में खोदो। बीस-बीस रुपये में एक कुंआ खोदा गया। विधान सभा की बैठक चल रही थी। मैं भी सदस्य था। जब इसकी आवाज उठी तो सरकार ने कहा इसकी जांच होगी। जब जांच हुई तो आप जानते हैं कि 20 रुपये में कितने कुएं खोदे जा सकते हैं। जब जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी जांच के लिये गये तो जो गड्ढे खोदे गये थे उनमें गांव सभापति ने घड़ों से पानी भर दिया। इस तरह से पिछली सरकार की योजनायें चला करती थीं। बाढ़ के नाम पर अरबों रुपया इस देश में बरबाद किया गया है और बाढ़ की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं हुआ है जिन नदियों का हमारे पूर्व वक्ताओं ने उल्लेख किया है वे देश की भयंकर नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र भयंकर विनाश लीला करती है। इसी तरह से हमारे उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी और गंगा नदियां भी भयंकर विनाश लीला करती हैं। इनकी विनाश लीलायें देखी नहीं जा सकती हैं। पिछले 42 वर्षों में अरबों रुपये खर्च किये, लेकिन इन पर नियंत्रण नहीं पाया गया है। अरबों रुपयों की योजनायें बनाई गई, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों को लन्दन जाने का और विदेश में जाने का मौका मिला होगा। मुझे भी इसी जुलाई में एक डेलीगेशन के साथ लन्दन जाने का अवसर मिला। टेम्स नदी जो लंदन के बीच से बहती है मान्यवर, उसके दोनों तटबंध पक्के बनाये गये हैं। बीच लंदन शहर से नदी बहती है लेकिन कभी बाढ़ का प्रभाव नहीं। उसी के किनारे वहां की पार्लियामेंट है, उसी के किनारे पूरा लंदन शहर है लेकिन कभी एक इंच पानी प्रभावित नहीं करता। आज जो छोटी-छोटी नदियां शहरों के किनारों से, कस्बों के किनारों, गांवों के किनारों से निकलती हैं वह उन पूरे के पूरे शहरों, कस्बों और गांवों को बरबाद कर देती हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि पूरे के पूरे गांव बह जाते हैं। पांडेय जी चले गये। मैं चाहता था कि वे यहां पर बैठते। क्या योजनायें इसके लिये पिछली सरकार ने बनाई? क्यों नहीं इस बाढ़ की विभीषिका को आज तक रोका गया? मान्यवर, इसको न करने के कारण आज यह समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। मान्यवर, मैं आपका समय नहीं लेना चाहता। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

मान्यवर, पिछली सरकार ने निश्चित ही कुछ योजनायें

[श्री ईशदत्त यादव]

बनाई थी। लेकिन उस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार अपनी चरमसीमा पर था। ढ़ाब के नाम पर, राहत के नाम पर, सूखा के नाम पर जो भी पैसा जिले तक गया, प्रखंड तक गया, ब्लाक तक गया, जहां भी वह पैसा पहुंचा, वह सब अधिकारियों की जेब में चला गया। मान्यवर, जिले के अधिकारी, प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी तो मनौती मांगते हैं, तमन्ना करते हैं कि बाढ़ आये, सूखा पड़ जाये क्योंकि ऐसा होने पर उनके अच्छे दिन आ जाते हैं। जब बाढ़ आती है या सूखा पड़ता है तो राज्य कर्मचारियों के अच्छे दिन आ जाते हैं। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे आजमगढ़ जिले से घाघरा नहीं बहती है। महुला-गढ़वल बांध वहां बना है जो कि करीब 45 किलोमीटर लंबा है। तीन साल पहले यह हुआ कि ऐसा महसूस किया गया कि यह बंधा टूट जायेगा। अगर एक जगह पर भी वह बंधा टूट जाता तो उस स्थान से लेकर बलिया तक, जहां गंगा नदी बहती है कम से कम पांच सौ गांव साफ हो जाते, बाढ़ की चपेट में आ जाते। सरकार ने प्रयास किया, कांग्रेस सरकार ने, केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय दोनों सरकारों ने प्रयास किया और मेरी जानकारी में उस बंधे को टूटने से बचाने के लिये 10 करोड़ रुपया दिया गया। लेकिन वह सारा पैसा सरकारी कर्मचारियों की जेबों में चला गया और बंधा तो भगवान की कृपा से बच गया, टूटा नहीं।

महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए यह सुझाव देना चाहता हूं कि बाढ़ नियंत्रण के लिये सरकार को कोई स्थायी योजना बनानी चाहिये। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी जनता दल की सरकार, हमारे जल संसाधन मंत्री इस बारे में चिंतित हैं। वे चाहते हैं कि बाढ़ पर नियंत्रण हो ताकि बाढ़ के कारण देश की बरबादी न हो। मैं अपनी ओर से भी यह सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार इसके लिये कोई स्थायी योजना बनाये ताकि हर वर्ष बाढ़ नियंत्रण पर इस मुल्क का करोड़ों रुपया बरबाद न हो। इसलिये एक स्थायी योजना बनाकर इस बाढ़ की विभीषिका को रोका जाये।

दूसरा मेरा निवेदन है कि यह जो प्राकृतिक जल है, जो ऊपर से जल वृष्टि होती है, उसको इकट्ठा करने की योजना बनाई जाए। जब जल इकट्ठा होगा तो उससे कई लाभ होंगे। एक तो बाढ़ आगे नहीं बढ़ेगी, नदियां ज्यादा नहीं बढ़ेंगी और जगह-जगह पर अगर पानी को रोका जायेगा तो उससे सूखे की समस्या का भी मुकाबला किया जा सकता है। उस जल को एकत्रित करके उससे सिंचाई की जा सकती है।

मान्यवर, वैज्ञानिकों का कहना है कि पानी का धरातल दिनों दिन नीचे चला जा रहा है, वह नीचे खिसकता चला जा रहा है। अगर पानी को इस एक जगह पर केंद्रित किया जायेगा, इकट्ठा किया जायगा तो इससे पानी का धरातल नीचे नहीं जाने पायेगा। ऐसा न होने पर आगे आने वाले समय में भयंकर समस्याएं हो सकती हैं।

अंत में मैं जो सबसे आवश्यक सुझाव माननीय जल संसाधन मंत्री और सरकार को देना चाहता हूं वह यह है कि आप इसके लिये स्थायी योजना तो बनायें, बाढ़ पर नियंत्रण करने का प्रयास करें, लेकिन साथ ही इस पैसे का सही ढंग से सदुपयोग हो रहा है या नहीं, इसके लिये आप अलग से एक कमेटी बनायें।

इसके लिए आपको अलग से आयोग बनाना पड़ेगा और इसकी जांच पड़ताल और सर्वेक्षण करना पड़ेगा वरन् इस देश का पैसा उस बाढ़ के पानी में जैसे 42 साल से बहता चला गया है, उसी तरह से फिर बहता चला जाएगा और बाढ़ का नियंत्रण किसी तरीके से नहीं हो पाएगा। इन शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमती कमला सिन्हा के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बाढ़ एक विभीषिका का रूप है। उसी पानी, जिस पानी को हम कहते हैं कि जल जीवन है और पानी में जो नम्रता है कहीं-कहीं विद्वानों ने कहा है कि पानी नम्रता का प्रतीक है और पानी अग्नि को भी शान्त कर सकता है। *इतनी ताकत है इसमें। पानी लोगों के कलंक धोता* है। गंगा की महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। गंगा मैया के किनारे सारा साल लोग अपने दुख, अपने पाप और कलंक धोने के लिए स्नान करने के लिए जाते हैं। हमारी हिन्दू माइथोलोजी तो कहती है कि काशी का मुआ सीधा बैकुंठ जाए। कहीं-कहीं तो गंगा मैया का पानी लोगों के कलंक, दुख, अशान्ति और पाप धोते-धोते काला हो जाता है। इस मुल्क के साधु, संतों और महात्माओं की चरण-गंगा का पान कर के फिर से पवित्र होकर उत्सर्ग करता है और फिर से समाज को पवित्र करने की कोशिश करता है। एक तरफ आप और हम गंगा के पानी की इतनी महिमा गाते हैं परन्तु उसी गंगा का पानी जब बाढ़ के रूप में आता है तो प्रलय का रूप होता है, विभीषिका का रूप होता है, चण्डी का रूप होता है, नाश का रूप होता है और विनाश का रूप होता है। इससे बचने के लिए मैं किसी सरकार के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं। मैं सीधी सी बात करता हूं। अगर आप मुझे नंगा करते हो तो मैं आपको नंगा करता हूं।

हमने अपनी प्रकृति को नंगा किया है इसलिए प्रकृति ने हमें नंगा किया है। मैंने नार्थ बिहार में बाढ़ में रिलीफ बांटते हुए लोगों को देखा है। लोग छोटी-छोटी चट्टानों के टीलों पर बैठे हैं, बदन पर कपड़ा नहीं है, रात को सोए हुए थे, घर बह गया। क्योंकि प्रकृति को हमने नंगा किया था, हमने जंगलों को काट डाला, हमने ज़मीन के ऊपर से हरी चीज़ों का विनाश कर दिया, प्रकृति ने हम को नंगा कर दिया। आज उसका मूल कारण यह है कि हमारे दरियाओं में, हमारे डैम्ज़ में और हमारे रिज़र्वायर्ज़ में सिल्टिंग बढ़ती चली जा रही है। जंगल काटे जा रहे हैं जिससे हमारी जमीन का जो बंधन है वह टूटता जा रहा है। ज़रा सी बारिश होती है या ज़रा सी बर्फ पिघलती है तो पहाड़ों की मिट्टी लैंडस्लाइड के रूप में गिरती जाती है और नदियों का जहां बहाव है वहां सिल्ट जमती जाती है जिससे नदी की गहराई कम हो जाती है और फैलाव बढ़ता जाता है।

ईश दत्त जी लन्दन की टेम्स रिवर की बात कर रहे थे। वहां नदियों को सिल्टिंग से मुक्त करने के लिए बाकायदा मशीनें चलायी जाती हैं। हमारे मुल्क में अभी तक ऐसी मशीन नहीं जिनसे नदियों के बहाव को तेज करने के लिए और नदियों की गहराई को साफ करने के लिए कहीं कुछ किया जाता हो। इम्बैंकमेंट्स यहां भी बनते हैं। बड़े-बड़े बोल्डर्स फेंक कर, बड़े-बड़े ठेके देकर यहां भी नदियों को घेरने की कोशिश की जाती है। पर सारा व्यर्थ है क्योंकि सिल्टिंग होती जा रही है। यह ध्यान में रखने की बात है कि जिस भाखड़ा नांगल के डैम पर आज हमें गर्व है, कल हम रोएंगे क्योंकि उसकी डीसिल्टिंग नहीं की जाती है। जितने भी डैम हैं उनकी डीसिल्टिंग नहीं की जाती है और उनकी रिजर्विंग कैपेसिटी दिन प्रति दिन कम होती जा रही है। वह फैलता जा रहा है, गांवों को अपने घेरे में लेता जा रहा है और अपनी इम्बैंकमेंट में क्रेक डेवलप करके उनको बाढ़ से ग्रसित कर रहा है जिससे हम अफेक्टेड हो रहे हैं।

मैं बिहार से आता हूं और बिहार बागमती, सोन, गंडक, महानंदा और गंगा नदियों से ग्रसित होता है। कभी ये आशीर्वाद के फूल देते हैं, ये दरिया और उनका पानी और कभी-कभी विनाश के रूप में हमारे घरों में पानी आ जाता है। इस विनाश का सिर्फ एक कारण है। उपसभाध्यक्ष महोदय, हमें बहुत पुराने रास्तों पर लौटना पड़ेगा जब लोगों ने, संतों और महात्माओं ने कहा था और हमारे गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा गया है "पवन कुरु पाणी"।

पवन को तुम गुरु का रूप दो, पानी को तुम पिता का रूप दो, धरती को अपनी मां के समान मानो। जिस तरह से अपनी मां की रक्षा की जाती है उसी तरह से धरती की रक्षा करो। पिता की रक्षा जिस तरह से की जाती है उसी तरह से पानी की रक्षा करो और जिस तरह से गुरु का सम्मान किया जाता है उसी तरह से पवन का सम्मान करो, अर्थात् इन्वायरनमेंट को कंट्रोल करके रखो। इन्वायरनमेंट में बैलेंस रखो। अगर इन्वायरनमेंट में बैलेंस नहीं रखोगे तो इस तरह की विभीषिका का सामना करना पड़ेगा और ऐसे प्रलय देखने पड़ेंगे।

नेपाल के लोगों ने जंगल के जंगल काट दिये। नेपाल के पहाड़ों पर जब पानी आता है तो इतनी मिट्टी साथ में लाता है कि हमारे सारे दरियाओं की गहराई को भर देता है और यह गहराई कम होने के कारण यह पानी पूरे नार्थ बिहार में एक विभीषिका का रूप लेकर लाखों लोगों को घर से बेघर कर देता है। श्रीमती कमला सिन्हा एक बहुत अच्छा सुझाव, एक प्रस्ताव लाई हैं और आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि इन्वायरनमेंट डिपार्टमेंट और वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट दोनों को क्लब कर देना चाहिए। दोनों मिनिस्ट्रीज एक हो जानी चाहिएं क्योंकि दोनों एक हिसाब से जुड़ी हुई हैं। पर आज इन्वायरनमेंट को अलग रखा है। जब हम इन्वायरनमेंट को कंट्रोल करेंगे तभी बाढ़ को कंट्रोल कर सकते हैं।

एक और प्रस्ताव अपनाने की जरूरत है कि जहां भी नंगी जमीन हो।

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार): अर्थ शास्त्र की भाषा में बोलें। साहित्य की भाषा में बोल रहे हैं।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: अर्थशास्त्र मैंने आपके लिए छोड़ दिया है क्योंकि आंकड़ों में ही आप फंसे रहेंगे।

श्री राम अवधेश सिंह: उसी की जरूरत है।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: लोहिया जी ने जो आंकड़े सिखाये हैं उन्हीं आंकड़ों में फंसे रहेंगे।

श्री अश्विनी कुमार: अर्थशास्त्र छोड़ा है कि अनर्थ शास्त्र?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: मेरी सीधी-सीधी बात है कि जहां-जहां नंगी जमीन है वहां ग्रीन पैचेज होने चाहिए, वहां पर हमें ट्रीज प्लांट करनी चाहिए, उसको हरा भरा रखना चाहिए क्योंकि तभी वह

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

जमीन को पकड़कर रख सकती है। आप बाहर की बात छोड़िये। आप लम्बी-चौड़ी बात छोड़िये। आपके अपने घर के सामने जहां घास लगी हुई है, बारिश होती है, तो मिट्टी बाहर नहीं जाती। अगर घास नहीं लगी हुई है, तो मिट्टी बह करके चली जाती है।

एक माननीय सदस्य: फाडर मशीन की जरूरत है।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: मैंने पहले ही कहा था कि मैं राजनीति के पीछे नहीं पड़ना चाहता। अगर आप फाडर मशीन पर आ रहे हैं, तो मैं बंगाल लैम्प पर आ सकता हूं। मुझे देर नहीं लगेगी। अगर आप चाहते हैं बंगाल लैम्प और ट्राम की बात सुनना, तो मैं कह सकता हूं। मेरे पास इनफर्मेशन की कमी नहीं है।....**(व्यवधान)**

आपको मेरी शक्ति का मालूम है।

तो महोदय, मेरी सीधी सी बात है कि यह दोनों मंत्रालय क्लब का दिये जाएं और प्रकृति को नंगा होने से बचाया जाए। प्रकृति को नंगा होने से अगर हम बचायेंगे, तो प्रकृति हमें नंगा होने से बचायेगी और ऐसी विभीषिका हमारे सामने नहीं आएगी।

मैं यही कहते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अश्विनी कुमार: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, श्रीमती कमला सिन्हा जी ने जो बिहार की बाढ़ की स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए प्रस्ताव रखा और सुझाव रखा और मेरे माननीय सहयोगी ने जो उस पर विचार दिये, वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं।

जब बिहार की स्थिति का वर्णन करते हैं, तो मैं उस समय का आपको वर्णन करना चाहता हूं कि जब स्वतंत्रता के पूर्व बाढ़ की बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएं बिहार में नहीं बनी थीं, हर वर्ष बाढ़ आती थी।

नदियों में पानी जब भरता था, तब धीरे-धीरे चढ़ता था, बाढ़ आती थी। तो जो इधर बिहार के गांव हैं दरभंगा, इत्यादि के, वहां लोग चौकी रखते थे और चौकी को वह घड़े के साथ बांध कर रखते थे। पानी चढ़ता था, चौकी ऊपर हो जाती थी। तो उस पर अपना सामान रखते थे। थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे पानी आता था। वह बाढ़ कुछ देर टिक करके 2, 4, 5 या 10 दिन के बाद बैठ जाती थी। नई मिट्टी चढ़ जाती थी। बाढ़ हमेशा आती थी। बाढ़ पर कोई नियंत्रण नहीं था।

परन्तु जो विभीषिका आती थी, लोगों की जो बर्बादी होती थी, वह तो होती ही थी, लेकिन जिस प्रकार की बर्बादी आज हो रही है वैसी नहीं थी, उसकी वजह से वह सिल्ट चढ़ जाती है। हमने पाशचात्य सभ्यताओं से जो संस्कृति, इंजीनियरिंग ली, वहां से टैक्नालोजी ली, उसका भारतीयकरण नहीं किया। अंधानुकरण करके हमने बाढ आने वाली नदियों के ऊपर बड़े-बड़े बांध बना दिया। मैं उसकी चर्चा बाद में करुंगा। उनका रख-रखाव आज ठीक नहीं है। उसकी भी चर्चा मैं बाद में करुंगा।

अब क्या होता है? बाढ़ आती है, जमीन नीची है, एक्वैमेंट काफी ऊंचा है, खटाक से कहीं 20, 30 या 40 फुट का दरार पड़ता है और इतनी जोर से नदी बहती है कि गांव के गांव, मवेशी आदि बहते-बहते, पता नहीं किस रसातल में चले जाते हैं, यह बाढ़ बिहार की पुरानी संस्कृति का भाग नहीं रहा है। परंतु जो विभीषिका, जो नाश आज हो रहा है कि इन सारे संसाधनों के बाद यह भयंकर है, क्योंकि इस प्रकार से नदी एकदम से आकर चलती है और भयंकर विभीषिका होती है।

हमने स्वाधीनता के बाद बड़ी-बड़ी योजनाए बनाई और योजना बना कर के, जैसे दो बड़ी योजनाएं गंडक और कोसी है बिहार के अंदर बाढ़ की नियंत्रण की दृष्टि से।

बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन योजनाओं को आज से 15 से लेकर 20 साल हो गये हैं, पर क्या सरकार कह सकती है कि वह योजनाएं पूरी हो गई है? आज भी वह योजनाएं पूरी नहीं हुई है और उस क्षेत्र में घूमने के कारण मैं बता सकता हूं कि वराज बन गया है, बड़ी-बड़ी नहरें बन गई हैं, नहरों के साथ नहरें जुड़ गई हैं, बड़े-बड़े काम हो गये है, परंतु कनेक्ट करने के लिए छोटे से साईफन चाहिएं। वह नहीं बने हैं। कहीं सौ फुट का पैच पड़ा है, कहीं एक मील का पैच पड़ा है, इससे पानी इधर उधर जाता है। यह छोटे काम पूरे न करने के पीछे जो निहित स्वार्थ है, वह काम कर रहे हैं। योजनाएं नई-नई हैं और भारत सरकार के जो आंकड़े हैं, आनगोईंग प्लांस के ऊपर 85 हजार करोड़ रुपये ब्लाक पड़े हैं। जो आज हमारे पास विदेशी कर्जा है, जिसकी हम इतनी चर्चा करते हैं अपने बजट के अंदर, 85 हजार करोड़ रुपये हमारी इन योजनाओं में ब्लाक्ड पड़े हैं, जो हमें उसका रिटर्न नहीं दे रहे हैं जो हमको उसका फल नहीं दे रहे हैं और उसमें से अधिकांश बड़े-बड़े इरीगेशन प्रोजैक्ट्स के ऊपर हमारे पैसे फंसे हुए हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमने जो बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाईं और उनके जो मैं आपके सामने उदाहरण रखना चाहूंगा जिस प्रकार से उनकी प्लानिंग की गई, उस योजना में दोष था। योजना है 100 करोड़ की

और 5 साल में पूरी होनी चाहिए। इसका मतलब है पहले साल 20-30 करोड़ रुपया इसके लिए प्रोवाइड किया जाना चाहिए लेकिन प्रोवाइड 5 करोड़ रुपया किया गया। कहां से वह 5 साल में पूरी होने वाली है? पांच करोड़ में से चार करोड़ एस्टैब्लिशमेंट पर खर्च हो गया। सरकारी अधिकारी पूरे हैं। उनका ताम-झाम पूरा है। उनकी जीपें भी दौड़ रही हैं, उनमें पेट्रोल भी जल रहा है। उनके टेलीफोन भी चल रहे हैं। उनके भत्ते भी बन रहे हैं। पर काम क्या हो रहा है?

दूसरे एक मुद्दे की ओर, मंत्री जी यहां बैठे हैं, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह है योजना के अन्दर उसके अधिकारियों की नियुक्ति के ऊपर। जब पांच साल की योजना है तो आप ऐसे अधिकारी को क्यों नहीं उसका चीफ इंजीनियर, जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डाइरेक्टर बनाकर भेजते हैं, जिसको आठ साल में रिटायर करना है। सीनियर मोस्ट आदमी जाता है जिसको साल भर में रिटायर होना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस व्यक्ति का क्या उस योजना के साथ लगाव है? वह तो कहता है कि मैं तो साल भर यहां से मक्खन काटने आया हूं और घूस खाकर घर चला जाऊंगा। मुझे तो रिटायर होना है। आने वाला भुगतेगा सो भुगतेगा। मुझे क्या लेना है। उसके बाद 6 महीने तक पोस्ट खाली रहती है। 6 महीने के बाद दूसरा पोस्ट होता है। वह डेढ़ साल के लिए पोस्ट होता है। इस प्रकार से 6 महीने तक पोस्ट खाली, फिर सीनियर मोस्ट आया। उसका कोई उसके अन्दर लगाव नहीं और उसके कारण योजना असफल रहती है। पहली योजना की दिक्कत शुरू होती है फाइनांस डिपार्टमेंट से। योजना पांच साल की, सौ करोड़ की और आपको 20 करोड़ तो कम से कम देना चाहिए, वहां 5 करोड़ दिया। अधिकारी ऐसे दिए जाते हैं जिनका इन्टरेस्ट नहीं होता। इनके चलते ये आज भ्रष्टाचार के केन्द्र बन गए हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, बिहार के अन्दर जहां तक नदियों की बाढ़ का प्रश्न आया, मेरे सम्माननीय मित्र चले गए, उन्होंने नेपाल की चर्चा की। बिहार की सारी नदियां जो उत्तर बिहार से आती हैं सोन इत्यादि को छोड़ दिया जाए तो नेपाल से आती है। नेपाल प्राकृतिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से एक प्रकार से भारत का अंग है। जब हम भारत माता की कल्पना करते हैं उसमें हिमालय का अपना शीर्ष मस्तिष्क मानते हैं। उस मस्तिष्क को काट कर दूसरी जगह दे दें और शरीर यहां रह जाए तो ऐसी माता की कल्पना कहां से होगी। ठीक है, राजनीतिक दृष्टि से वह हम से अलग हो चुका है, परन्तु कोई भी बाढ़ की योजना इस देश में चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, वह तब तक सफल नहीं हो सकती है जब तक नेपाल सरकार का उसके अन्दर अंश या योगदान नहीं लेते हैं। मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है, नेपाल के साथ हमारी सब प्रकार की आत्मीयता है, आज हम उसको अपना एक अंग मानते हैं। भारत माता के अन्दर हिमालय को हम मस्तिष्क मानते हैं, परन्तु जब से नेपाल में राणा राज्य गया वहां पर फिर से प्रजातंत्र का स्वरूप बना एक प्रकार से राज्य आया जिसको बनाने में भारत ने संपूर्ण योगदान दिया अभी के प्रजातंत्र की स्थापना में भी हमने योगदान दिया, परन्तु हमारी जो भी केन्द्र की सरकार रही है उसकी जो भी विदेशी नीति रही है वह नेपाल और अपने पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने में पूर्णतया असफल रही है और असफलता का भार हमारे सिर पर आता है। आज सब इंजीनियर्ज़ कहते हैं, इनवायरंमेंट्स के एक्सपर्ट्स कहते हैं नेपाल और भारत की मिल कर योजना बनेगी तब तो हो सकता है, वहां पर जंगल लगें, वहां पर बराज बनें। बराज के कारण उनकी धरती डूबेगी, उसका मुआवज़ा हम दें। उसकी हम बिजली बनाएं। बिजली बना कर अगर आज वहां पर बराज बना दें भारत अपने सहयोग से तो हमारी बाढ़ रुकती है। करीब-करीब 17 हजार मेगावाट बिजली नेपाल बना सकता है जो सारे भारत में खपेगी उसके संसाधन बनेंगे। 17 हजार मेगावाट का अर्थ है उसको करीब-करीब 50 हजार करोड़ रुपया सालाना बिजली का दाम देंगे। अब बिहार में आप बाढ़ की कल्पना कर रहे हैं। बाढ़ के साथ-साथ जरा आप बिहार में जा कर देखिए। बिजली की हालत यह है कि अगर किसी समय आएगी, किस समय जाएगी इसका प्रश्न नहीं है, आती ज्यादा है या जाती ज्यादा है, इसके लिए भी एक सर्वे चाहिए पटना सरीखे शहर में एम०एल०ए० फ्लैट्स के अन्दर रहने के बावजूद भी कितनी बिजली आएगी, जाएगी, दो घंटे दिन में बिजली आ गई तो हम भाग्य मानते हैं और अगर एक दिन 24 घंटे बिजली नहीं गुल हुई तो हम कहते हैं कि भाई, आज क्या बात हो गई? बिहार बदल गया है क्या, जो बिजली नहीं गई? बिजली की हालत सारे बिहार में एकदम निष्कृष्ट है। बहुत बड़े-बड़े शहर हैं मुज़फ्फरपुर है, रांची है, इंडस्ट्रियल टाउन्ज़ हैं जहां बिजली नहीं है। हम बिजली के लिए हाहाकार कर रहे हैं, वह पानी बहा कर हमको बाढ़ हमारे ऊपर आ रही है और वहां बिजली बहती चली जा रही है और इसके लिए उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन कहना चाहूंगा बाढ़ की स्थिति अगर बिहार और उत्तर प्रदेश की हम ठीक करना चाहते हैं, आसाम की ठीक करना चाहते हैं तो हम को नेपाल के साथ

[श्री अश्विनी कुमार]

मिलकर, उनके पर्यावरण को ठीक करने के लिए, उनको जंगल लगाने के लिए प्रेरणा देनी पड़ेगी। उनकी जो जमीन डूबेगी उसका कम्पनसेशन देना होगा, उनको बड़े-बड़े डैम बनाने के लिए हम को सारा सहयोग देना पड़ेगा, हम को इंटरनेशनल ट्रीटी करनी पड़ेगी। वहां से नियंत्रण करना होगा क्योंकि पानी का टेप तो वहां से खुलता है तो यहां हम कैसे रोक लेंगे। यहां हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो कुछ भी हम ने किया है, वह आज तक अपूर्ण रहा है। अब जब बाढ़ के ऊपर हमारे यहां हर साल करोड़ों-अरबों रुपये खर्च होंगे। बड़ी-बड़ी योजनाओं पर, गंडक और कोसी पर कितना खर्च हुआ है, मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वह हम को उत्तर में बताएं। ये आंकड़े सदन के सामने मंत्री महोदय की ओर से आने चाहिएं। अब हमारे बड़े-बड़े एम्बैंकमेंट बन गए, जिनका मैंने पहले वर्णन किया। बिहार सरकार के ऊपर उन एम्बैंकमेंट्स का उत्तरदायित्व है। उपाध्यक्ष महोदय, आप को जानकर आश्चर्य होगा पिछले 4-5 साल से बिहार सरकार के इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर बाढ़ के जो एम्बैंकमेंट हैं, इनके रखरखाव का जो बजट है वह 15-20 करोड़ तक गया है। महोदय, 15-20 करोड़ रुपया सालाना खर्च होता है और ये एम्बैंकमेंट टूटते हैं। यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह है और जब इसकी खोजबीन में लगे तो पता चला कि इस 15-20 करोड़ में से एस्टेब्लिसमेंट का खर्चा 14 से 19 करोड़ रुपया है। वहां चीफ इंजीनियर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, एक्जेक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, ओवरसियर और कैजुएल लेबर हैं। 20 में से 19 करोड़ रुपया उनकी जीप और दूसरे खर्च पर, अब एक करोड़ में क्या होगा। फिर उस में हमारे यहां कुछ वलनरेब पाइंट्स हैं जैसे गंगा के तट पर मानसी पुल है, वहां हर साल कटाव होता है। वहां कुछ बड़ी योजना बन सकती है, परंतु पिछले कई वर्षों से हम लोग कह रहे हैं कि वहां स्थाई तटबंध बनने चाहिएं। लेकिन स्थाई तटबंध की योजना सरकार स्वीकार नहीं करती है। उसके लिए उतना पैसा नहीं है। उसमें केन्द्र सरकार और बिहार सरकार का प्रश्न है। वह गंगा की योजना है, मानसी रेलवे स्टेशन है जोकि बहुत बड़ा जंक्शन है। उसके बचाव की योजना है। उसके लिए स्थायी योजना बनने के बजाय हर साल करोड़, दस करोड़ रुपए के वोल्डर और बल्लियां उस में डाल दी जाती हैं। छोटे-छोटे तार के घेरे बांधकर उन में वोल्डर डाल दिए जाते हैं। इनकी कोई गिनती नहीं है, कितनी बल्लियां डाली गयीं, इसकी कोई गिनती नहीं हैं , कितने सैन्ड बैग डाले, इसकी कोई गिनती नहीं हैं। उस पोस्टिंग के लिए सुपरीटेंडिंग इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर रुपया देने के लिए तैयार हैं। यह हर साल का किस्सा है। आप कभी भी इंक्वायरी कराकर देख लीजिए। मैं एक स्थान का नाम रख रहा हूं, ऐसे वहां पर दर्जनों स्थान हैं जोकि भ्रष्टाचार के केन्द्र बने हुए हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि वही इंजीनियर हमारे पास आते हैं और हम ही मिनिस्टर साहब से कहते हैं कि उन्हें नॉन वर्क्स से वर्क्स में मानसी में पोस्ट कर दीजिए। इस में उनका क्या अर्थ है, यह हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। अगर आप इस समस्या का स्थाई समाधान खोजने के लिए नहीं आएंगे तो बाढ़ की विभीषिका से हम जल्दी छुट्टी नहीं पा सकते हैं।

अब जहां तक बाढ़ का आज प्रश्न आ गया है, उत्तर बिहार में कहावत हो गयी है कि सारे देश में दो फसल होती हैं—रबी और खरीफ। उत्तर बिहार में तीन फसल होती हैं—रबी, खरीफ और रिलीफ या तो बाढ़ होगी, या सुखाड़ होगा और उस की जो रिलीफ बंटेगी, वह भी एक फसल है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि वह रिलीफ कितने व्यक्तियों तक पहुंचती है। जितने सरकारी अधिकारी होते हैं—बी०डी०ओ० होते हैं, कलेक्टर होता है और ऊपर से नीचे तक पहुंचती है। अब यह एक प्रश्नवाचक चिह्न है कि उस में से कितनी जरूरतमंद तक पहुंचती है। यह रिलीफ एक मजाक और भ्रष्टाचार का केन्द्र बन गयी है। इसे यदि आप को समाप्त करना है तो आपकी सरकार को कुछ कदम उठाने हैं तो स्थायी और लंबी योजनाएं बनानी पड़ेंगी और तब जाकर आप कुछ कर सकेंगे अन्यथा यह ऊपर से लीपा-पोती से बिहार की स्थिति ठीक नहीं होगी। अभी हमारे मित्र ने कहा कि डिसिल्टेशन की भी योजना है। डिसिल्टेशन की मशीनें भी हैं, फरक्का से लेकर पटना तक हैं, परंतु उपसभाध्यक्ष महोदय आप को आश्चर्य होगा कि हम अगर कहीं नाव से सारा गंगा क्षेत्र घूम आएं, हमको डिसिलटिंग मशीन नहीं दिखेगी, परन्तु हम सरकारी अधिकारी को लिख दें तो वह जरूर हमको चलती हुई दिखा देगा। वे मशीनें कहां हैं? कितने में ली गई हैं? नई हैं या पुरानी? चलती हैं या नहीं चलती हैं? ये सारे प्रश्न-वाचक चिह्न हैं, जिन पर सोच-विचार कर ध्यान देने की आवश्यकता है।

महोदय, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मेरे पूर्व वक्ता ने भी कही, कि हमारी आबादी बढ़ रही है। स्वाधीन हम हुए तो बांगला-देश, पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में मिला कर 40 करोड़, जो आज सौ करोड़ से ऊपर जा चुकी है, केवल भारत में ही अस्सी करोड़ है और अगले दस वर्ष में यहां एक सौ करोड़ तक पहुंचने

की संभावना है। आबादी के साथ-साथ समस्याएं बढ़ रही हैं, जिसमें जमीन की भी आवश्यकता बढ़ रही है, जिसके लिए हम जंगल काट रहे हैं। पाश्चात्य पद्धति, जो पाश्चात्य सिस्टम है अमरीका का, जो पाश्चात्य सिस्टम है रूस का, उसकी ओर कुछ लोग आकर्षित हुए हैं। इनके यहां तो जनसंख्या कम है, क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है और ये तीन सौ, चार सौ साल पुराने देश हैं, जबकि हमारा देश हजारों साल पुराना है। यह भी प्रश्न वाचक चिह्न है कि यह देश एक हजार साल पुराना है या दस हजार साल पुराना है। उस समय कौन सी योजनाएं थीं कि जनसंख्या बढ़ी होते हुए भी हमारा पर्यावरण ठीक था, हम सारी समस्याओं को ठीक रख सके, सोचने की जरूरत है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पश्चिम की जो आज की संस्कृति है, उसके अनुसार भगवान ने मनुष्य को इस पृथ्वी पर भेजा है उपभोग करने के लिए । पश्चिम की संस्कृति यह है कि मनुष्य यहां उपभोग करने के लिए आया है, प्रकृति का शोषण करो। पश्चिम में प्रकृति का शोषण होता है अपनी सुख-सुविधा के लिए। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को माता माना गया है मां का शोषण नहीं हो सकता है, दोहन को सकता है, वह जितना दूध देगी, उतना दूध पीकर हम जीवित रह सकते हैं। मां के टुकड़े नहीं कर सकते। इसलिए हमारे यहां की संस्कृति में, जिसका आज के पढ़े-लिखे पाश्चात्य विद्वान मजाक उड़ाते हैं, आज फिर झक मार कर वहां आ रहे हैं। हमारी संस्कृति में गाय की पूजा होती है, पेड़ की पूजा होती है, जानवरों की पूजा होती है। पेड़ों की पूजा यानी उनको बनाकर रखना, पर्यावरण को बनाकर रखना। आज समस्या केवल बाढ़ की नहीं है, एनर्जी की समस्या आ रही है। आज देश के अंदर 70 फीसदी ऊर्जा की पूर्ति पेड़ों से हो रही है। हमारे जो एनर्जी एक्सपर्ट हैं, वे यह कहते हैं कि बीस साल बाद, दस साल बाद हम हर गांव में खाने के लिए आटा, दाल, चावल तो पहुंचा देंगे, लेकिन रोटी बनाने के लिए लकड़ी कहां से लाएंगे? यह हमारे सामने एक प्रश्न-वाचक चिन्ह है, जिस पर सोचना-विचारना होगा। यह बाढ़ की समस्या भी सीधी पर्यावरण से जुड़ी हुई है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, बिहार हर साल बाढ़ से त्रस्त होता है और जिस साल बाढ़ से त्रस्त नहीं होता, उस साल सुखाढ़ से त्रस्त हो जाता है। इन दोनों समस्याओं के संबंध में, मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा, जैसा कि मैंने प्रारंभ किया, पिछले साल, दो साल की कटुता के बाद नेपाल से हमारे संबंध मधुर हुए हैं, वहां प्रजातंत्र की स्थापना होने की एक संभावना दिख रही है मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, यह केवल जल-संसाधन मंत्री का प्रश्न नहीं है, सरकार का प्रश्न है इसमें आगे आने की आवश्यकता है, सबसे ज्यादा तो आप इसके अंदर एफेक्ट होते हैं, फायदा तो सबका होने वाला है, इसलिए सबको मिलाकर एक लंबी योजना आप बनाइए और इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार को भी योजना में सम्मिलित कीजिए। इस ओर आप बढ़ें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहन कमला सिन्हा के प्रस्ताव को समर्थन करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि इसके समाधान की योजना वह शीघ्र बनाए। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर): श्री सुरेश पचौरी।

श्री राम अवधेश सिंह: *उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं* आपसे निवेदन कर चुका हूं मुझे मौका दिया जाए, मुझे जाना है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) पचौरी जी के बाद आपको मौका दे दूंगा।

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, श्रीमती कमला सिन्हा ने जो गैर-सरकारी संकल्प यहां प्रस्तुत किया है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण और सामयिक है। इस गैर-सरकारी संकल्प को मैं अत्यंत महत्वपूर्ण और सामयिक इसलिए बोल रहा हूं कि जब इस पर चर्चा हो रही है तो न केवल बिहार के जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं या हुए हैं, उनके बारे में हो रही है अपितु उन सारे औपचारिक कदमों के बारे में विचार-विमर्श हो रहा है, जिनको अपनाने से सारे देश की जनता के लिए कुछ किया जा सकेगा, जो जनता बाढ़ की चपेट में आती है।

मान्यवर, केन्द्रीय जल आयोग में हमारे देश की लगभग 147 ऐसी नदियों के क्षेत्र हैं जिन्हें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है और यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इन 147 बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से 36 केवल बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। इसका तात्पर्य यह है कि बिहार सबसे ज्यादा बाढ़ की चपेट में आता है। तो इसलिए बिहार के लोगों को बाढ़ से मुक्ति मिल सके और बाढ़ आने पर वहां के लोगों के लिए कुछ इस ढंग के औपचारिक कदम उठाए जा सकें कि उन लोगों को राहत पहुंच सके वहीं इस बारे में भी विचार किया जाना बहुत आवश्यक है कि बाढ़ से इस देश की जनता को कैसे

मुक्ति दिलाई जा सके। इसके लिए जो बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम हैं उनका सही ढंग से नौकरशाहों के द्वारा कार्यान्वयन होना बहुत जरूरी है और इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि केन्द्र राज्यों के साथ भेदभाव पूर्ण व उपेक्षाभरी नीति न अपनाए।

मान्यवर, अक्सर यह देखने में आया है, मेरे पास आंकड़े हैं कि राज्यों ने जितनी राशि की मांग केन्द्रीय सरकार से बाढ़ से निपटाने के लिए की थी, उसके अनुपात में बहुत कम राशि राज्य सरकारों को दी गई। मिसाल के तौर पर आन्ध्र प्रदेश ने 271.56 करोड़ रुपये की मांग की थी, उसे केवल 28.76 करोड़ रुपये दिए गए। जम्मू-कश्मीर ने 111.87 करोड़ रुपये की मांग की थी, उसके केवल 14.46 करोड़ रुपये दिए गए। केरल ने 92.86 करोड़ रुपए की मांग की थी, उसे केवल 10.55 करोड़ रुपए दिए गए। राजस्थान ने 32.78 करोड़ रुपए की मांग की थी, उसे केवल 8.49 करोड़ रुपये दिए गए। वैस्ट बंगाल ने 125.53 करोड़ रुपए की मांग की थी, उसे केवल 23.56 करोड़ रुपये दिए गए। इसलिए मैंने कहा कि केन्द्रीय सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति बाढ़ से निपटाने के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों के प्रति नहीं होनी चाहिए, यह ध्यान देना बहुत आवश्यक है।

मान्यवर, बाढ़ से जो प्रति वर्ष हानि होती है, वह लगभग 400 करोड़ रुपए की होती है। पिछले वर्ष का जो आकलन है वह लगभग 386 करोड़ रुपए का है। 1988 में सबसे अधिक नुकसान हुआ जिसमें कि लगभग 50000 लोगों की जानें गई और 38 लाख पशु मारे गए जिससे कि 91 लाख हैक्टेयर भूमि प्रभावित हुई, वह कृषि क्षेत्र का केवल 38 लाख हैक्टेयर क्षेत्र है। तो इस प्रकार जब एक नेशनल कमीशन बना तो इसको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया—एक एग्रीकल्चरल फील्ड और दूसरी नान एग्रीकल्चरल फील्ड और उन्होंने यह पाया कि नान एग्रीकल्चरल फील्ड में जो पशुओं की हानि होती है जिससे कि रोड का नुकसान होता है, रोड उजड़ जाते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो जाता है, कई घर गिर जाते हैं, उसके साथ-साथ जो छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज लगी हैं, जहां से लोगों को रोजगार मिलता है, वह सारी चीजें प्रभावित होती हैं, पब्लिक यूटिलिटी प्रभावित होती है। इन सब पर हुए डेमेज को भी यदि देखा जाए, उसका जब आकलन किया जाए कि बाढ़ की वजह से क्या-क्या क्षति हुई तो वह न केवल कृषि के क्षेत्र में आंका जाना चाहिए बल्कि इन सब क्षेत्रों में भी क्षति का आकलन किया जाना बहुत जरूरी है। इन सब बातों पर गौर करने पर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बाढ़ के आने से जहां जन-जीवन प्रभावित होता है, जहां लोगों की जानें जाती हैं, जहां पशुओं की जानें जाती हैं, जहां ये सारे सिस्टम बिगड़ते हैं, जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, वहीं साथ ही साथ देश की आर्थिक क्षति भी होती है, देश की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती है और जब किसी देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है तो उस देश में जो सरकार चल रही होती है उसका यह दायित्व होता है कि उस पर वह गंभीर चिंता व्यक्त करे और कुछ ऐसे उपाय निकाले जिससे कि देश की आर्थिक क्षति न हो सके। इसके लिए मान्यवर, मेरा सुझाव है कि एक गारलैंड स्कीम होनी चाहिए। गारलैंड स्कीम से मेरा मतलब यह है कि विभिन्न प्रदेशों की जो नदियां हैं, वह एक माला में पिरो देनी चाहिए।

महोदय, इसका जिक्र पहले भी हुआ था। इसके बारे में हमारे जो विशेषज्ञ हैं वह यह कहते हैं कि गारलैंड स्कीम को लागू करने में काफी पैसा लगेगा लेकिन फिलहाल जो बाढ़ की वजह से आर्थिक हानि होती है उसके अनुपात में जितने पैसे इस स्कीम में लगेंगे वह उससे कम होंगे। साथ ही साथ जो दूसरे राज्यों में तनाव होता है, नदियों के जल के उपयोग को लेकर आपस में जो आंशिक तनाव अलग-अलग राज्यों में होता है उसमें भी कमी आएगी और एक राज्य की नदी का जल दूसरे राज्य में समुचित रूप से उपयोग में लाया जा सकेगा और उसका वैस्टेज नहीं होगा। वरना अभी क्या होता है कि कई नदियों का पानी समुद्र में चला जाता है और हम उसका सिंचाई में प्रापर उपयोग नहीं कर पाते हैं लेकिन इस स्कीम के लागू होने से नदियों के जल का भी समुचित प्रयोग होगा और साथ ही साथ जो आंशिक तनाव अलग-अलग राज्यों के बीच हो जाता है उसमें भी कमी आएगी।

मान्यवर, अभी तक जो कृषि की हानि का आकलन इस बाढ़ के परिणामस्वरूप किया गया है वह लगभग 70 से 80 प्रतिशत है। जहां हमारे देश में 70 फीसदी जनता ऐसी है जो कि कृषि करती है वहीं बाढ़ की वजह से यदि 70 से 80 प्रतिशत की हानि हो तो यह एक गंभीर विषय माना जाना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। महोदय, साथ ही मुझे यह भी कहना है कि फ्लड की वजह से जो क्रॉप की हानि होती है उसके इंश्योरेंस के लिए भी कुछ स्कीम्स बननी चाहिए और लागू होनी चाहिए।

महोदय, हमारे देश में न केवल बाढ़ की ही गंभीर समस्या है बल्कि साथ ही साथ सूखे की भी गंभीर

समस्या है। जब हम इन समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं तो यदि ऐसा कुछ हो जाए कि सूखे और बाढ़ से संबंधित एक अलग मंत्रालय की स्थापना हो जाए तो उससे कोआर्डिनेशन में काफी आसानी होगी। अभी क्या हो रहा है कि जो अलग-अलग कोआर्डिनेटिंग एजेंसीज हैं जैसे अलग-अलग हमारे कमीशन बने, अलग-अलग कमेटीज बनीं जैसे कि 1952 में एक नेशनल पालिसी बनी थी मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन एंड पावर की और उसकी जो रिकमंडेशंस रहीं उस पर अभी तक सही रूप से अमल नहीं हो पाया और साथ ही राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1976 में बना। उसने अपनी सारी सिफारिशें 1980 में दे दीं। उन सिफारिशों के प्राप्त होने के बाद भी उन उपायों का अभी तक सही कार्यान्वयन नहीं हो पाया।

इसके लिए वांछनीय यही है कि अलग से एक मंत्रालय बन जाए क्योंकि जैसा मैंने पहले ही कहा है कि बाढ़ से तकरीबन सभी मिनिस्ट्रीज प्रभावित होती हैं जैसे— मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ वैटरनिरी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविऐशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग आदि। ये सारे मंत्रालय जब इस बाढ़ से प्रभावित होते हैं तो यदि एक अलग मंत्रालय इसके लिए बना दिया जाए तो विभिन्न कोआर्डिनेटिंग एजेंसीज के बीच में सामंजस्य रहेगा, ऐसा मेरा ख्याल है।

महोदय, साथ ही कुछ साइंटिफिक प्रोसीजर्स के बारे में भी हम लोगों को विचार करना चाहिए ताकि इन वैज्ञानिक तरीकों की मदद से अभी जो बाढ़ के कारण क्षति हुई है उसका आकलन किया जा सके। मान्यवर, जैसा मैंने कहा कि लगभग 147 ऐसी नदियां हैं जो जिन क्षेत्रों से गुजरती हैं उनको बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया है। तो ये नदियां तो आईडेंटिफाईड हैं। लेकिन उनके आस-पास जो गांव आते हैं, उससे जो क्षेत्र प्रभावित होता है तो उसके लिए अगर ऐसा सिस्टम कर दिया जाए कि बाढ़ आने से पहले और बाढ़ आने के बाद उस क्षेत्र की क्या स्थिति थी, वहां पर रिहैबिलिटेशन के लिए और जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके लिए क्या कदम उठाए गए हैं, यदि इन सबके एसेस्मेंट की प्रापर व्यवस्था हो जाए तो मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा काम होगा। महोदय, यहां पर साथ ही साथ प्रिकॉशनरी मैजर्स लेना भी बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा कि बाढ़ आने से पहले उन क्षेत्रों की क्या स्थिति है, इसका एसेसमेंट जरूरी है वैसा ही मौसम विज्ञान का सहारा लेकर प्रिकाश्नरी मेजर अपनाया जाना काफी जरूरी है और उसके लिये ऐसा भी प्रोविजन किया गया कि फाइनेन्सियल और टैक्नीकल क्या असिस्टेंस दी जा सकती है। अगर एक अलग मंत्रालय होगा तो उसकी बेसिक और फंडामेंटल जो रिसर्च वर्क है वह किया जा सकता है और इसके लिये जो नेशनल पौलिसी 1954 में बनी थी उसमें इस चीज का जिक्र था और उसके आधार पर एक बोर्ड बना था। उसमें भी जिक्र था कि इस तरह का उपाय किया जाना जरूरी है। लेकिन उस पर भी अभी तक कोई अमल नहीं हो पाया है, ऐसा मेरा सोचना है। मान्यवर, जो हमारे देश की संरचना है वह अलग-अलग ढंग की है। कई इसमें पर्वत हैं, कई नदियां हैं जहां अलग-अलग धर्म और भाषा के अपनाये जाने वाले लोग हैं, वहीं हमें इस चीज को स्वीकारना चाहिए। जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि नदियां हमारे देश की जो हैं वह हमारे देश की लोक मातायें हैं और हमारे देश की आर्थिक उन्नति हो, यह इस चीज पर निर्भर करता है कि नदियों के जल का हम किस ढंग से उपयोग कर पायें और जैसा मैंने कहा कि यदि हम लोग गारलैंड स्कीम को लागू कर देंगे तो उससे नदियों के जल का सही उपयोग हो पायेगा, साथ ही साथ बाढ़ से जो प्रभावित लोग हैं, यानी प्रिकौशनरी मेजर सही ढंग से अपना लिये गये तो बाढ़ से जो प्रभावित लोग हैं न केवल उनको मुक्ति दिला पायेंगे बल्कि हमारे देश की तरक्की हो पायेगी, विकास हो पायेगा, ऐसा मेरा सोचना है। इसलिये आदरणीय श्रीमती कमला सिन्हा जी ने जो गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया है वह अति महत्वपूर्ण है।

SHRI MD SALIM: Mr. Vice-Chairman, Sir, as the flood changes the landscape, the speeches of my predecessors have completely changed the perspective of the Resolution which was initially on the devastating flood situation in Central and North Bihar. Actually, flood and drought have become household names in the everyday life of an average Indian. This is not something different from the failures of the successive governments in different fields. Even after 43 years of Independence, we have failed to control the flood situation in our country, be it in Bihar, be it in Assam or West Bengal or Madhya Pradesh or Western India.

हमारे जो कुलिग अब तक अपनी बात रखे हैं, यह अच्छे ढंग से, तकनीकी और फाइनेंसियल के बारे में काफी बहस कर चुके हैं, मैं इन तमाम बातों पर नहीं

[Shri M.D. Salim]

जाऊंगा। मेरा कहना यह है कि हम जब भी बल्कि यह आशंका है कि इस तरह की बात करते हैं जिसके साथ हमारे देश की जनता का दुखड़ा जुड़ा हुआ है तो फिर हम मांगें करते हैं, स्कीम की बात करते हैं, मास्टर प्लान की बात करते हैं, कुछ कमेटी या आयोग बनाया जाये जो दौरा करे और उसके बाद कुछ सिफारिशें हों, फिर कुछ हजारों-करोड़ों रुपये की लागत हो, टैंडर हों, कांट्रेक्ट हों, फिर उसकी मरम्मत के लिये जो गलती हमने रुपये खर्च करके की उसके सुधार के लिये फिर कोई रिव्यू कमेटी हो और इसी तरह से आजादी के पहले से ही बाढ़ के बारे में भी हमारा सोच-विचार इसी तरह का रहा, जिसकी वजह से हमारे देश में आज इस वक्त कच्छ के किसान आसमान की तरफ देखकर अल्लाह मेघ दे पानी दे, करके चीख रहे हैं। बिहार से आये हुये हमारे साथी इनको बिहार के सैलाब के बारे में, बाढ़ के बारे में संकल्प उठाना पड़ रहा है। यह हमारे देश की जो समस्यायें हैं इसको सही ढंग से निबटाने के बारे में हमारी जो नाकामी है इसे हमें मान लेना चाहिये।

हम जब यहां बहस में हिस्सा ले रहे हैं तो हमें संकल्प के साथ इस बात को देखना पड़ेगा कि जैसा हमारे कुछ साथियों ने बाढ़ के बारे में हिस्सा लेते समय नजरिया पेश किया था उससे लगता है कि जैसा गरीबी को लेकर हम राजनीति करते हैं वैसा ही बाढ़ को लेकर भी करते हैं, रिलीफ को लेकर भी करते हैं बल्कि यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अच्छी खासी राजनीति करने का मौका मिल जाता है। पिछले कई वर्षों में हमने देखा है कि जब भी सूखा पड़ा, या बाढ़ आयी चाहें आन्ध्र प्रदेश में हो, चाहें पश्चिमी बंगाल में हो, चाहें बिहार में हो तो सरकारी पैसे से, सरकारी हेलीकॉप्टर में, सरकारी हवाई जहाज में दौरा करके हम चुनावी प्रचार कर लेते हैं। इसलिए बाढ़ रोकने की बजाय हर चुनावी साल से पहले कम से कम एक बार अच्छी-खासी बाढ़ पूरे देश में आ जाए ऐसा हमारे बहुत से राजनीतिक नेता प्रार्थना करते हैं। मैं बंगाल से आया हूं जो मध्य बिहार और उत्तरी बिहार से जुड़ा हुआ है जब वहां बाढ़ आती है तो वह बंगाल को भी लपेट में ले लेती है। चाहें वह नेपाल से आया हुआ पानी हो, उत्तर प्रदेश से या बिहार की नदियों का पानी हो। हम जब कभी सुबह-शाम बात करते हैं बंगाल में कितना पानी हो रहा है तो उससे ज्यादा समय जाता है बिहार प्लेट्यू में कितना पानी हो रहा है। प्लेट्यू में ज्यादा पानी है तो दक्षिण बंगाल डूब जायेगा। हम समझते हैं कि जो जुड़ी गई राज्य सरकारें हैं उन सरकारों से बातचीत करके केन्द्रीय सरकार को ही कोई कदम उठाना है लेकिन वह कदम डी०वी०सी० जैसा न हो।

हमें एक बात और ध्यान देनी होगी कि चाहे बाढ़ रोकने का मामला हो, सूखे को रोकने का मामला हो जब भी कोई मामला लेते हैं तो मास्टर प्लान के बारे में सोचते हैं। हम रुपये की तादाद, अमाउंट के बारे में सोचते हैं कि कितने हजार रुपये की लागत आयेगी। हमारे देश में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार आने के बाद एक नया मौका मिला है। हम उस चीज को रुपये की नजर से न देख कर हमारे देश की जो नौजवान शक्ति है उस नजर से देखते हैं। ऐसी मिसाल हमारे सामने हैं। हमारे यहां राइट टु वर्क की बात होती है फिर भी हर साल बाढ़ में हम डूबे रहते हैं। 13 करोड़ हमारे यहां बेरोजगार हैं, अनआफिशियली। हमारे पास 26 करोड़ हाथ हो गये। हम 26 करोड़ हाथ का इस्तेमाल करके 26 नदियों पर क्या बांध नहीं बना सकते? लेकिन अफसोस यह है कि हम नहीं कर पा रहे हैं। अगर ब्रिटिश के जाने के बाद हम इस नजरिये से सोचते, हम ऐसा काम करते तो इसको रोकने का बंदोबस्त कर सकते थे। अभी कम से कम कोई स्कीम ऐसी लाएं, जैसे पंचायती व्यवस्था है उसका इस्तेमाल करें। हमारे बंगाल में इससे लाभ हुआ है बांध बनाने में। हम केन्द्रीय सरकार के साथ बैठ कर प्लान बनायें लेकिन उसका इम्पलीमेंटेशन जब हो तो उसके बारे में जो पंचायती व्यवस्था है....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Salim, would you be able to conclude within one minute?

SHRI MD. SALIM: I will just take another one-and-a-half minutes. I am going to conclude.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI

BHASKAR ANNAJI MASODKAR): I am asking because we have to adjourn at 5 p.m. If you are going to conclude just now, it is all right. Otherwise, you can continue next time. I am not hurrying you. You can take your time. You can continue your speech on the 24th which is the next non-official day for Resolutions.

SHRI MD. SALIM: Thank you.

5.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): He will continue on 24th. That is the day allotted for the Private Members' Resolutions.

Now I want the leave of the House whether we should take up special mentions. There are 11 special mentions but I do not see more than one or two Members who are present.

SHRI SYED SIBTEY RAZI (Uttar Pradesh): We should start it.

SHRI T. A. MOHAMMED SAQHY: Everybody has to go. Let us adjourn.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): The suggestion is that we should postpone this because many of the Members want to go.

SHRI SYED SIBTEY RAZI: Sir, two or three Members are there and they have waited for the whole day for this.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): All right, I will go according to the serial. Shri Bal Ram Singh Yadava, not there. Shrimati Bijoya Chakravarty, Shrimati Margaret Alva, Shri Ahluwalia, not there. Shri Surendra Singh Thakur.

SPECIAL MENTIONS

Acute Shortage of Cooking Gas in Madhya Pradesh

श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर (मध्य प्रदेश): आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि एक छोटी-सी बात, लेकिन अत्यन्त महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से सरकार के समाने रखने का आपने मुझे मौका दिया है। भोपाल में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में, कुकिंग गैस की भारी कमी व्याप्त है। कंज्यूमर्स परेशान हैं। महीनों तक नम्बर लगाने के बाद भी गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही है। मालूम करने पर बताया गया कि गैस की सप्लाई चूंकि कम है इसलिए डीलर्स असमर्थ हैं कंज्यूमर्स को गैस प्रदान में। मुझे मालूम नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कुकिंग गैस पर भी राशनिंग की हुई है और अगर ऐसा नहीं है तो क्या कारण है कि गैस की पूरी सप्लाई नहीं हो रही है? आपकी सरकार जब से सत्ता में आई है, कंज्यूमर्स पर चारों ओर से लगातार मार पड़ रही है। उसी दिशा में यह कदम भी है जिसके कारण लोगों को गैस भी उपलब्ध नहीं हो रही है। मैंने जब इसकी गहराई में जाकर मालूम करने की कोशिश की तो कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनमें नितान्त सुधार की आवश्यकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे देश में तीन नेशनलाइज्ड आयल कार्पोरेशन्स हैं जो लोगों को गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम डीलर्स के माध्यम से करते हैं। इंडियन आयल कार्पोरेशन जिसके 16 सौ वितरक हैं, एच०पी०सी० जिसके 12 सौ वितरक हैं और बी०पी०सी०एल० जिसके 7 सौ वितरक हैं। इनके माध्यम से पूरे देश में गैस का वितरण किया जाता है। शिकायत इस बात की मिली है कि इन कम्पनीज में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। इनमें जो बल्क डिस्ट्रिब्यूशन होता है वह भी असमान है। जैसे 16 सौ वितरक वाली कम्पनी जिसकी पात्रता 46 प्रतिशत है उसको 50 प्रतिशत दिया जाता है और जिसकी पात्रता 34 प्रतिशत बल्क प्राप्त करने की है उसको सिर्फ 25 प्रतिशत दिया जाता है और बी०पी०सी० जिनकी पात्रता 20 प्रतिशत प्राप्त करने की है उसको भी 25 प्रतिशत दिया जा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो इस असमानता को दूर किया जाये और दूसरे जो गैस कम्पनियों में कोआर्डिनेशन की आवश्यकता है उसको ठीक किया जाये।

एक और महत्वपूर्ण बिन्दु है और वह यह है कि जो सिलेन्डर्स की फीलिंग की जाती है वह अलग अलग कम्पनियों की अलग अलग स्थानों पर की जाती है। और उसके कारण से, मान लीजिये भोपाल में अगर तीन कंपनीज है तो एक की भोपाल में फिलिंग होती है, दूसरे की बड़ौदा में और तीसरे की इंदौर के पास। तो मेरा निवेदन है कि यह जो फिलिंग वाला कार्य है, क्योंकि ये तीनों ही सरकार की कंपनियां हैं तो इनकी एक ही जगह से फिलिंग की जाय। इसके अभाव से करोड़ों रुपया सरकार का ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो रहा है। इसलिये यह जरूरी है कि इसको रोका जाय। इसके कारण कंज्यूमर्स